वर्ष : 16 ❖ अंक : 333 ❖ पृष्ठ : 08 ❖ मूल्य : ₹ 3.00 ❖ आरएनआई सं. SIKHIN/2006/17890 ❖ www.anugamini.com

सिक्किम से प्रकाशित प्रथम हिन्दी दैनिक

अनुगामिनी

गंगटोक
रविवार, 17 जुलाई 2022

आठ सालों में लाखों किसानों की आय हुई दोगुनी : नरेंद्र तोमर 3

'रेवड़ी कल्चर' देश के विकास के लिए घातक : पीएम मोदी 8

वीआईपी वाहनों के कागजातों की भी करें जांच : मंत्री खरेल

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 16 जुलाई । राज्य परिवहन विभाग तथा सड़क सुरक्षा परिषद के अन्य सम्बंधित विभागों द्वारा शुक्रवार को स्थानीय यातायात भवन में एक सड़क सुरक्षा काउंसिल मीट तथा सड़क सुरक्षा माह, 2022 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया।

गौरतलब है कि सड़क सुरक्षा पर उच्चतम न्यायालय की समिति और केंद्रीय सड़क परिवहन व उच्चपथ मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार परिवहन विभाग राज्य सरकारों को जारी किये गये दिशा-निर्देशों पर एक कम्प्लायंस रिपोर्ट जमा करने को बाध्य है। उक्त बैठक में राज्य के भवन व आवास तथा परिवहन मंत्री संजीत खरेल मुख्य अतिथि एवं लोकसभा सांसद इंद्रहांग सुब्बा सम्मानीय अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे।

वहीं बैठक में शामिल प्रतिभागियों का प्रदेश परिवहन प्राधिकरण के सचिव सह प्रधान मुख्य अभियंता मनीष प्रधान तथा परिवहन विभाग के सचिव राज यादव ने स्वागत किया। वहीं उनलोगों ने सिक्किम पुलिस, सड़क व सेतु विभाग, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आरएमडीडी, बीआरओ, एनएचआईडीसीएल, यूडी एवं एचडी समेत अन्य सम्बंधित विभागों द्वारा आवश्यक सड़क सुरक्षा कार्यों की स्थिति का भी जायजा लिया। बैठक में सभी जिलों के जिला कलेक्टरेट तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालयों के अधिकारी भी शामिल हुए।

इस दौरान मुख्य अतिथि भवन व आवास मंत्री संजीत खरेल ने सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की औपचारिक घोषणा की।

वहीं अपने वक्तव्य में इस आयोजन हेतु विभाग की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा कार्यों की प्रगति पर खुशी जतायी। इस दौरान उन्होंने आरटीओ को वीआईपी वाहनों समेत सभी सरकारी वाहनों के कागजातों की भी समुचित जांच करने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने जांच प्रक्रिया को शैक्षणिक एवं सूचना आधारित होने के साथ ही पहली गलती पर जुर्माना न लगाये जाने की भी बात कही।

इस अवसर पर सांसद एवं कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर इंद्रहांग सुब्बा ने अपने वक्तव्य में सड़क सुरक्षा मुद्दे पर स्कूली बच्चों को शिक्षित करने पर जोर देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रमों के आयोजन की जरूरत बतायी। बैठक का समापन अतिरिक्त परिवहन आयुक्त केएस गुरुंग के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ।

नड्डा ने किया ऐलान

जगदीप धनखड़ एनडीए के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट

राजेश अलख

नई दिल्ली, 16 जुलाई । पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ आगामी छह अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार होंगे। राजधानी स्थित पार्टी मुख्यालय में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सर्वोच्च नीति निर्धारक ईकाई संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने यह घोषणा की।

प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, किसान पुत्र जगदीप धनखड़ राजग के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी होंगे। धनखड़ जी, एक साधारण किसान परिवार से आते हैं। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए अपने जीवन में उच्च लक्ष्य को प्राप्त किया और देश की सेवा करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी।'' उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में धनखड़ ने लोगों के दिल पर राज करने वाले राज्यपाल के रूप में पहचान बनाई। संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और नड्डा के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित संसदीय बोर्ड के अन्य सदस्य मौजूद थे।

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 19 जुलाई है और मतदान छह अगस्त को निर्धारित है। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। देश के उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं।

संसद में सदस्यों की मौजूदा संख्या 780 है, जिनमें से केवल भाजपा के 394 सांसद हैं। जीत के लिए 390 से अधिक मतों की आवश्यकता होती है। भाजपा ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है। यदि मुर्मू चुनाव जीत जाती हैं, तो वह देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। राजग ने 2017 में उपराष्ट्रपति पद के लिए तत्कालीन केंद्रीय मंत्री नायडू को अपना उम्मीदवार बनाया था। भाजपा इस बार भी अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए मजबूत स्थिति में है।

80, 90 पूरे 100? 'मज़बूत रुपये के लिए एक मज़बूत प्रधानमंत्री की ज़रुरत है' रुपये में गिरावट को लेकर राहुल गांधी का हमला

नई दिल्ली, 16 जुलाई (एजेन्सी)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में गिरावट को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि अब सरकार को अपनी कुम्भकर्णीय नींद से जागकर आर्थिक नीतियों में सुधार करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में शुक्रवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 17 पैसे की मजबूती के साथ 79.82 रुपये पर पहुंच गया। वीरवार को रुपया गिरकर 80 के पार चला गया था। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि80, 90 पूरे 100?

प्रधानमंत्री बनने से पहले रुपये की कीमत पर लंबे-लंबे प्रवचन देते थे, लेकिन पीएम बनने के बाद, देश को पाखंड के अमृतकाल' में धकेल दिया है। इतिहास में पहली बार, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुक़ाबले सबसे कमज़ोर - 80 पार हो चुका है। उन्होंने कहा कि रुपये की जर्जर हालत और दिशाहीन सरकार के कारनामों का भुगतान आने वाले दिनों में देश की जनता को करना पड़ेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा था कि 'मज़बूत रुपये के लिए एक मज़बूत प्रधानमंत्री की ज़रुरत है'। उस जुमले की हक़ीक़त आज सबके सामने है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं भारत सरकार से फिर कह रहा हूं, अभी भी वक़्त है, अपनी कुम्भकर्णीय नींद से जाग जाओ। झूठ और जुमलों की राजनीति बंद करो, और तुरंत आर्थिक नीतियों में सुधार करो। आपकी नाकामियों की सज़ा देश की आम जनता नहीं भुगत सकती।

पवन चामलिंग का सिलीगुड़ी में हुआ नागरिक अभिनंदन

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 16 जुलाई । नेपाल सरकार के शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत डिल्लीराम-कल्याणी रेग्मी मेमोरियल लाइब्रेरी डेवलपमेंट कमेटी की ओर से नेपाली भाषा तथा साहित्य के माध्यम से पूरी दुनिया में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करते हुए सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री तथा एसडीएफ अध्यक्ष पवन चामलिंग को 6 जुलाई को काठमांडू में डॉ डिल्लीराम रेग्मी इंटरनेशनल पीस प्राइज-2078 से सम्मानित किया गया। इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के बाद नेपाल के कई सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थानों और हस्तियों ने काठमांडू के विभिन्न सभागारों में पवन चामलिंग को सम्मानित किया था।

वहीं नेपाल से लौटते समय विभिन्न नेपाली भाषी सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थानों ने 14 जुलाई को सिलीगुड़ी के मैनाक टूरिस्ट लॉज में पवन चामलिंग नागरिक का नागरिक अभिनंदन किया गया। भानुभक्त समिति, मंगल माइती, देवकोटा संघ, अमुक्त परिवार, दुर्गागढ़ी दुर्गा जनकल्याण समिति, बालकृष्ण संघ, समाज सेवा समिति, साठ प्लस, अखिल भारतीय मगर संघ, भारतीय गोरखा मंच, अखिल भारतीय किराती संघ, मानव मौलिक अधिकार संघ के साथ ही पश्चिम बंगाल के बुद्धिजीवियों, पूर्व सैन्य अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से पवन चामलिंग का अभिनंदन किया गया।

इस अवसर पर स्वागत भाषण भारतीय गोरखा मंच के अध्यक्ष राम छेत्री ने दिया, जबकि मंच के सचिव खेम सापकोटा ने पवन चामलिंग की संक्षिप्त जीवनी और कार्यों पर एक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में धन्यवाद प्रस्ताव भानुभक्त समिति के महासचिव कृष्ण लामा (पेम्बा) ने दिया, जबकि कार्यक्रम का संचालन सुश्री अंजना भंडारी ने किया।

उल्लेखनीय है कि नेपाल सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला यह अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला (2006), भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (2007), पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर (2008), स्विस नागरिक टोनी हेगन (2009), संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून (2011), म्यांमार की लोकतांत्रिक नेता आंग सान सू की (2013), अमेरिकी नागरिक जॉन वुड (2015), 'रूम' के संस्थापक टू रीड'', यूनेस्को (2017) और 'रीड नेपाल'' और 'रीड ग्लोबल'' के संस्थापक डॉ. एंटोनिया न्यूवर (2019) को सम्मानित किया गया है। पवन इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार को पाने वाले पहले नेपाली हैं।

साहित्य के क्षेत्र में पवन चामलिंग ने अपनी युवावस्था से ही कलम चलाना शुरू कर दिया था, साथ ही अखबारों का प्रकाशन, पुस्तकालय की स्थापना और पुस्तकों का प्रकाशन भी शुरू कर दिया। उनके सम्पादकत्व में सन् 1977 से साहित्यिक पत्रिका 'निर्माण' का प्रकाशन शुरू हुआ तथा इसी वर्ष निर्माण प्रकाशन की स्थापना भी हुई। निर्माण प्रकाशन के माध्यम से पारिजात, इंद्र बहादुर राई, अगम सिंह गिरी, भीमनिधि तिवारी, अच्छा राई रसिक, महानन्द पौडयाल की कई कृतियों के प्रकाशन के साथ-साथ सैकड़ों मूल्यवान साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। पवन चामलिंग ने स्वयं असंख्य कविता संग्रह, गीत संग्रह, गद्य लेखन आदि प्रकाशित हुए हैं।

राष्ट्रपति चुनाव : सिक्किम के मतों का मूल्य सबसे कम, यूपी का सबसे अधिक

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 16 जुलाई । देशभर के निर्वाचित विधायक राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए सोमवार को मतदान करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के विधायकों का मत मूल्य सबसे अधिक होगा, जबकि सिक्किम के विधायकों का मत मूल्य सबसे कम होगा। वहीं, सांसदों का मत मूल्य उनसे कहीं अधिक 700 होता है।

उत्तर प्रदेश के 403 विधायकों में से प्रत्येक का मत मूल्य 208 है, यानी उनका कुल मूल्य 83,824 है। तमिलनाडु और झारखंड के प्रत्येक विधायक का मत मूल्य 176 है। इसके बाद महाराष्ट्र का 175, बिहार का 173 और आंध्र प्रदेश के हरेक विधायक का मत मूल्य 159 है। तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा का कुल मत मूल्य 41,184 है और झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा का कुल मत मूल्य 14,256 है।

महाराष्ट्र विधानसभा के 288 विधायकों का मत मूल्य 50,400 है और बिहार विधानसभा के 243 सदस्यों का मत मूल्य 42,039 है। वहीं, 175 सदस्यीय आंध्र प्रदेश विधानसभा का कुल मत मूल्य 27,825 है। किसी विधायक का मत मूल्य 1971 की जनगणना के अनुसार उस राज्य की कुल आबादी के आधार पर गिना जाता है। छोटे राज्यों में सिक्किम के प्रत्येक विधायक का मत मूल्य सात है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का मत मूल्य आठ-आठ, नगालैंड का नौ, मेघालय का 17, मणिपुर का 18 और गोवा का मत मूल्य 20 है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के एक विधायक का मत मूल्य 16 है।

सिक्किम में 32 सदस्यीय विधानसभा का कुल मत मूल्य 224, मिजोरम विधानसभा में 40 सदस्यों का मत मूल्य 320, अरुणाचल प्रदेश के 60 विधायकों का मत मूल्य 480, नगालैंड के 60 सदस्यों का मत मूल्य 540, मेघालय के 60 सदस्यों का मत मूल्य 1,020, मणिपुर विधानसभा के 60 सदस्यों का मत मूल्य 1,080 और 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा का मत मूल्य 800 है।

वहीं, संसद के एक सदस्य का मत मूल्य 708 से घटाकर 700 कर दिया गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी कोई विधानसभा नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव में किसी सांसद का मत मूल्य राज्य विधानसभाओं और दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर समेत केंद्र शासित प्रदेशों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या के आधार पर तय होता है।

राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य तथा राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य शामिल होते हैं।

अगस्त 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित होने से पहले जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा की 83 सीटें थीं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी जबकि लद्दाख पर केंद्र सरकार का शासन होगा।

दो दिवसीय रांके मेला शुरु

अनुगामिनी का.सं.

नामची, 16 जुलाई । आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज नामची के सेन्ट्रल पार्क में प्रसिद्ध रांके मेला का शुभारम्भ हुआ। धूमधाम से आयोजित किये जाने दो दिवसीय इस मेले के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही 'तकिया लड़ाई' एवं अन्य परम्परागत स्थानीय खेलों का भी आयोजन होगा।

रांके मेला समारोह आयोजन समिति के साथ ही जिला प्रशासनिक केंद्र, पर्यटन व खेल विभाग तथा सिक्किम ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित इस मेले में कई कृषि-सब्जियों की प्रदर्शनी, परम्परागत फूड प्लाजा, ग्रामीण खेलकूद, रांके पुतला दहन एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा मेले में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों तथा किसान उत्पादक संगठनों द्वारा जैविक सब्जियों तथा फूलों के स्टॉल भी लगाये गये हैं।

वहीं मेले में बाजार परिसर में सरकारी सूचना व जनसम्पर्क, पर्यटन, इंडियन हिमालयन सेंटर फॉर एडवेंचर एंड ईको टूरिज्म चेमचे, नामची स्मार्ट सिटी लिमिटेड, कृषि व बागवानी विभाग आदि के स्टॉल भी स्थापित किये गये हैं।

जानकारी के अनुसार कल रविवार को मेले के समापन अवसर पर कई खेल आयोजनों का फाइनल मैच खेला जायेगा। इसकी विजेता-उपविजेता टीमों को पुरस्कृत भी किया जायेगा।

अपने अधिकारों को लेकर जागरुक बनें उपभोक्ता : जिलाधिकारी ठटाल

अनुगामिनी का.सं.

गेजिंग, 16 जुलाई । आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राज्य के खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के कानूनी नापतौल इकाई तथा उपभोक्ता सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा आज सोरेंग वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के सभागार में एकदिवसीय उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर बागवानी व कृषि बोर्ड के अध्यक्ष सीके राना मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। उनके अलावा कार्यक्रम में राज्य उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग के सदस्य डीपी शर्मा, सोरेंग जिलाधिकारी भीम ठटाल, अतिरिक्त खाद्य व आपूर्ति सचिव श्रीमती डिकी डोमा भूटिया, सोरेंग सीनियर सेकेण्डरी स्कूल के प्रिंसिपल डॉ. पीबी छेत्री, एलएमयू एवं सीपी सेल की उपनिदेशक के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे।

जानकारी के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षक-शिक्षिकाओं व गैर-शिक्षक कर्मचारियों और स्थनीय लोगों को उपभोक्ता विषय जागरुकता लाने के उद्देश्य से ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों को उपभोक्ता अधिकारों, पैकेज्ड वस्तुओं के लेबलिंग मापदंड, अधिकतम खुदरा मूल्य की समस्या, ई-कॉमर्स वेबसाइटों से ऑनलाइन खरीददारी, आईएसओ मानकीकरण, आईएसआई मार्क, उत्पादन कम्पनियों के लिये नियमों, खाद्य सुरक्षा, प्रयोगशाला गतिविधियों, हॉलमार्किंग आदि से सम्बंधित जानकारियां दी गयीं।

कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सनों ने उपभोक्ताओं को कानूनी अधिकारों के जागरूक किया। साथ ही ऑनलाइन ठगी से बचने हेतु बीआईएस के मोबाइल ऐप 'बीआईएस केयर' को डाउनलोड करने की सलाह दी। इस दौरान एलएमयू एवं सीपी प्रकोष्ठ के उप-निदेशक तितास बसनेत ने उपभोक्ता अधिकारों के अलावा एकीकृत बाल विकास, मध्यान्ह भोजन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के बारे में कई उपयोगी जानकारियां दीं। उन्होंने 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना के बारे में भी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्रदान किया।

वहीं यहां अपने वक्तव्य में जिलाधिकारी भीम ठटाल ने उपभोक्ताओं से अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्याद भुगतान न करने और अपने अधिकारों के प्रति अधिक से अधिक सूचनाएं एवं जानकारियां प्राप्त करने को कहा। उन्होंने उपभोक्ताओं से ठगी जैसे मामलों की सूचना प्रशासन त पहुंचाने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रशासन की ओर से सभी सहयोग किया जायेगा। वहीं डीसीएसओ (उत्तर) पालदेन एन. लाचुंग्पा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, ओएनओआरसी तथा पीएम-जीकेएवाई के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि नया कानून योजनाओं के तहत सभी को सुविधाएं प्रदान करता है। वहीं उन्होंने जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदत्त सुविधाओं की जानकारी दी। इसके अलावा कृषि व बागवानी (शेष पृष्ठ ०३ पर)

राज्य में कोविड के 114 नए मामले

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 16 जुलाई । पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में आज कोविड के 114 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही राज्य में कोविड के कुल मामलों की संख्या 39,876 हो गई। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड सकारात्मकता दर 24 प्रतिशत रही। इस दौरान कोविड के लिए 467 नमूनों की जांच की गई थी।

वहीं,मरने वालों की संख्या 460 पर अपरिवर्तित रही। नए मामलों में सबसे अधिक 64 मामले पूर्वी सिक्किम से दर्ज किए गए जबकि दक्षिण सिक्किम से 31, पश्चिम सिक्किम से 15 और उत्तरी सिक्किम से चार मामले सामने आए। छोटे हिमालयी राज्य में इस सप्ताह ताजा संक्रमणों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। इसने बुधवार को 68, गुरुवार को 70 और शुक्रवार को 87 मामले दर्ज किए थे।

वर्तमान में राज्य में कोविड के 489 सक्रिय मामले हैं। इस बीमारी से राज्य में अब तक 38,159 लोग ठीक हो चुके हैं और 768 दूसरे राज्यों में चले गए हैं।

सहिष्णुता लोकतंत्र का गहना है जो आज गायब हो गया, देश का माहौल चिंताजनक : गहलोत

जयपुर, 16 जुलाई (एजेन्सी)। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि देश में तनाव और हिंसा का माहौल चिंता पैदा करने वाला है और ये चिंता खत्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे आकर लोगों से शांति एवं सद्भाव बनाए रखने की अपील करनी चाहिए।

गहलोत ने कहा कि सहिष्णुता लोकतंत्र का गहना है जो आज गायब हो गया है। मुख्यमंत्री ने यहां 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरणों के दो दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एम वी रमण और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजीजू भी मौजूद थे। गहलोत ने देश में चुनी हुई राज्य सरकारों को गिराए जाने पर भी कटाक्ष किया और कहा कि देश के हालात बहुत नाजुक हैं, इस बारे में हम सबको सोचना होगा।

उन्होंने कहा कि हम बार-बार कहते हैं कि देश में तनाव है, हिंसा का माहौल है... यह नहीं होना चाहिए... लोकतंत्र सहिष्णुता पर टिका होता है। सहिष्णुता तो लोकतंत्र का गहना है... जो आज गायब है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, अगर वह कोई बात कहेगा तो देश सुनेगा... तो क्या प्रधानमंत्री जी को यह नहीं कहना चाहिए कि देश में भाईचारा, प्रेम-मोहब्बत, सद्भावना रहनी चाहिए और किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

गहलोत ने मंच पर आसीन रिजीजू से कहा वे उनकी इस भावना को प्रधानमंत्री मोदी तक पहुचाएं। गहलोत ने कहा कि यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि देश में आज ऐसा माहौल बन गया है जो चिंता पैदा कर रहा है और मेरा मानना है कि ये चिंता समाप्त होनी चाहिए। गहलोत ने कहा कि विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और न्यायाधीश, हम सब शपथ लेते हैं। अगर शपथ की मूल भावना को भी आत्मसात कर लें, उससे इधर-उधर (राइट-लेफ्ट) नहीं भटकें तो भी काम चल जाएगा। शपथ लेने के बाद भी हम लोग राइट-लेफ्ट' होते हैं तो संतुलन बिगड़ता है।

अदालतों में क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं को दें बढ़ावा, किरेन रिजिजू बोले- मानसून सत्र में रद्द होंगे 71 कानून

नई दिल्ली, 16 जुलाई (एजेन्सी)। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही में क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। स्थानीय अदालतों में क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिए जाने की वकालत करते हुए रिजिजू ने शनिवार को कहा, अदालत की भाषा अगर आम भाषा होगी तो हम कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कानून मंत्री ने कहा कि संसद के अगले सत्र में 71 अलग-अलग कानून निरस्त किए जाएंगे।

मंत्री ने कहा कि मातृभाषा को अंग्रेजी से कम नहीं आंका जाना चाहिए और कहा कि वह इस विचार से सहमत नहीं हैं कि एक वकील को अधिक सम्मान, मामले या फीस केवल इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि वह अंग्रेजी में अधिक बोलता है। रिजिजू ने कहा, उच्चतम न्यायालय में दलीलें और फैसले अंग्रेजी में होते हैं। लेकिन हमारा दृष्टिकोण यह है कि उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। रिजिजू ने यहां 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरणों के दो दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।

केंद्रीय कानून मंत्री ने देश की अदालतों में लंबित मामलों की बड़ी संख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि न्यायपालिका और सरकार को मिलकर इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। रिजिजू ने कहा कि न्याय का द्वार सबके लिए समान रूप से खुला होना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि सरकार और न्यायपालिका के बीच बहुत अच्छा तालमेल होना चाहिए, ताकि आम आदमी की सेवा करने, उसे न्याय दिलाने के लक्ष्य में कोई विलंब नहीं हो और कोई न्याय से वंचित नहीं रहे।

अदालतों में लंबित मामलों की संख्या पर चिंता जताते हुए रिजिजू ने कहा, आजादी के अमृत महोत्सव काल में देश की अदालतों में कुल लंबित मामलों की संख्या लगभग पांच करोड़ हो गई है। इन पांच करोड़ लंबित मामलों के समाधान के लिए न्यायपालिका और सरकार के बीच तालमेल से हर संभव कदम उठाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, कोई भी अदालत सिर्फ विशिष्ट लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी कारण आम आदमी को न्यायालय से दूर करता है तो वह हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। मैं हमेशा मानता हूं कि न्याय का द्वार सबके लिए खुला हो और सबके लिए बराबर हो।

अहमद पटेल पर लगे आरोपों को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर वार, कहा- दिवंगत को भी नहीं बख्शा

नई दिल्ली, 16 जुलाई (एजेन्सी)। कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि गुजरात पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) की ओर से दिवंगत नेता अहमद पटेल के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं।

कांग्रेस ने कहा कि यह 2002 के सामूहिक हत्या मामले में अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक व्यवस्थित रणनीति का हिस्सा है।

एसआईटी ने तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका का विरोध करते हुए गुजरात की अदालत के समक्ष दावा किया कि वह 2002 के दंगों के बाद राज्य में भाजपा सरकार को बर्खास्त करने की मंशा संबंधी

दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के इशारे पर की गई बड़ी साजिश का हिस्सा थीं।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान जारी कहा, कांग्रेस दिवंगत अहमद पटेल के खिलाफ गढ़े गए शरारतपूर्ण आरोपों को पुरजोर तरीके से खारिज करती है। यह प्रधानमंत्री की उस व्यवस्थित रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह 2002 में उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान हुई सांप्रदायिक सामूहिक हत्या को लेकर किसी भी जिम्मेदारी से खुद को बचाना चाहते हैं।

उन्होंने दावा किया, इस सामूहिक हत्याकांड को नियंत्रित करने की उनकी अनिच्छा और अक्षमता के कारण ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त के मुख्यमंत्री को राजधर्म की याद दिलाई थी।

रमेश ने कहा, प्रधानमंत्री की राजनीतिक प्रतिशोध वाली मशीन उन लोगों को भी नहीं छोड़ती जो उनके राजनीतिक विरोधी रहे और अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह एसआईटी अपने राजनीतिक आकाओं की धुन पर नाच रही है और उसे जो कहा जाएगा वही करेगी। हम जानते हैं कि पहले के एक एसआईटी प्रमुख को राजनयिक जिम्मेदारी से नवाजा गया क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दी थी।

उन्होंने दावा किया, न्यायिक प्रक्रिया के चलने के दौरान अपनी कठपुतली एजेंसियों के जरिए अनर्गल आरोप लगाकर प्रेस के माध्यम से फैसला सुनाना मोदी-शाह की तरकीबों की वर्षों से पहचान रही है। यह मामला कुछ नहीं बल्कि इसी की एक मिसाल, बस इतना है कि एक दिवंगत व्यक्ति को बदनाम किया जा रहा है जो ऐसे सरेआम बोले जा रहे झूठ को खारिज करने के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते।

उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस संक्रमण के बाद पैदा हुई स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण पटेल का 25 नवंबर, 2020 को निधन हो गया था।

सिक्किम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में वार्षिक खेल प्रतियोगिता आयोजित

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 16 जुलाई। सिक्किम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के एनएसएस प्रकोष्ठ द्वारा शुक्रवार को वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से मुख्य रूप से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण हेतु नेशनल सर्विस स्कीम (एनएसएस) योजना शुरू की गयी है। 'सेवा के माध्यम से शिक्षा' एनएसएस का मूल उद्देश्य है।

जानकारी के अनुसार 'कैम्पस के साथ कम्युनिटी' का सार्थक सम्बंध स्थापित करते हुए एनएसएस द्वारा इस प्रकार के खेल आयोजनों के माध्यम से विद्यार्थियों को नशे, एलजीबीटीक्यू जागरुकता, साइबर क्राइम, वयस्क तथा एड्स अधिकारों जैसे विभिन्न मुद्दों पर संदेश दिया जाता है। इसमें शामिल हरेक सेमेस्टर की देखरेख कॉलेज के फैकल्टी द्वारा की जाती है।

सिक्किम सरकार की स्टेट एनएसएस अधिकारी सुश्री ललिता छेत्री ने आज इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थीं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए विद्यार्थियों को समाज के प्रति एक सकारात्मक रवैया अपनाते हुए सामुदायिक स्तर पर खेलों में शामिल होने हेतु प्रोत्साहित किया। वहीं सिक्किम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. टीडी लामा ने भी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए विद्यार्थियों एवं शिक्षकों टीचिंग तथा लर्निंग पद्धति में खोजपरकता लाने को कहा।

सोमवार को राज्यसभा में पेश होगा सामूहिक विनाश के अस्त्रों से संबंधित विधेयक

नई दिल्ली, 16 जुलाई (एजेन्सी)। परिवार न्यायालय (संशोधन) और भारतीय अंटार्कटिक विधेयक को सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जबकि सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) संशोधन विधेयक को उसी दिन राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

दोनों सदन जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाह्यान और केन्या के तीसरे राष्ट्रपति मवाई किबाकी को भी श्रद्धांजलि देंगे जिनका निधन पिछले संसद सत्र के बाद हुआ है।

सदन की कार्य सूची के अनुसार, विदेश मंत्री एस जयशंकर सामूहिक विनाश के अस्त्रों से संबंधित विधेयक को राज्यसभा में पेश करेंगे।

विधेयक में सामूहिक संहार के आयुधों और उनके प्रसार के वित्त पोषण का निवारण करने के लिए केंद्र सरकार को निधियों एवं अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों या आर्थिक संसाधनों पर रोक लगाने, अधिग्रहण या कुर्की करने का अधिकार देने की बात कही गई है।

सदन की कार्य सूची के अनुसार, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू का नाम सोमवार को परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक को लोकसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध है।

कई राज्यों में काम कर रहे परिवार न्यायालयों को मान्य करने के लिए मसौदा कानून लाया गया है। केंद्र सरकार की किसी अनिवार्य अधिसूचना के अभाव के चलते दो राज्यों- नागालैंड और हिमाचल प्रदेश में विवाह संबंधी विवादों के त्वरित समाधान के लिए स्थापित पारिवारिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर प्रश्नचिह्न लग गया है।

कानूनी कठिनाई को दूर करने के लिए, सरकार दोनों राज्यों की पारिवारिक अदालतों में न्यायिक अधिकारियों और अदालत के कर्मचारियों की नियुक्ति को पूर्वव्यापी प्रभाव से मान्य करने में मदद करने के लिए यह विधेयक लेकर आई है।

छब्बीस राज्यों में 710 से अधिक परिवार न्यायालय काम कर रहे हैं।

इसी तरह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का नाम लोकसभा में भारतीय अंटार्कटिक विधेयक पेश करने के लिए सूचीबद्ध है।

विधेयक अंटार्कटिक संधि और इसके लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल को प्रभावी बनाने की बात कहता है।

यह ऐसे किसी भी व्यक्ति, पोत या विमान पर लागू होगा जो विधेयक के तहत जारी किए गए परमिट के तहत अंटार्कटिक क्षेत्र में भारतीय अभियान का हिस्सा है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का भूस्खलन पर जागरुकता कार्यक्रम

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 16 जुलाई। आजादी का अमृत महोत्सव 2022 मनाने के अवसर पर, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भुवनेश्वर की ओर से फेंगला में भूस्खलन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर बीएसएनएल के डीजी, स्थानीय पंचायत अधिकारी, बीआरओ कर्मी और क्षेत्र के निवासी शामिल हुए।

समूह के साथ अपनी बातचीत में, डॉ. पंकज सैनी, निदेशक और कार्यालय प्रमुख, जीएसआई एसयू: सिक्किम ने पूरे राज्य में भूस्खलन अनुसंधान में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण राज्य इकाई सिक्किम, गंगटोक की सक्रिय भागीदारी, भूस्खलन अध्ययन के विभिन्न तत्वों और भूस्खलन को रोकने के लिए उपयोग मे की जाने वाली शमन विधियों पर चर्चा की। प्रतिभागियों के साथ एक सकारात्मक आदान-प्रदान हुआ, और सभी सवालों के जवाब दिए गए। बैनरों की सहायता से भूस्खलन अनुसंधान में शामिल सभी अधिकारियों ने दर्शकों को जीएसआई द्वारा किए गए कई अध्ययनों के बारे में जानकारी दी। बातचीत हिन्दी, अंग्रेजी और नेपाली में आयोजित की गई थी।

कार्यक्रम के आयोजन के लिए निवासियों और स्थानीय सरकार के प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम के आयोजकों की प्रशंसा की।

हिंसक घटनाओं पर बोले सीएम योगी, उपद्रवियों को सबक सिखाओ

कानपुर, 16 जुलाई (एजेन्सी)। यूपी में पिछले कुछ दिनों से हो रही हिंसक घटनाओं को लेकर सीएम योगी ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। सीएम योगी को एक और हिंसक घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने अफसरों को सीधे तौर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मामला बिल्हौर में हुई हिंसक घटना का है। इसकी जानकारी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची तो उन्होंने अफसरों से कहा कि उपद्रवियों को सबक सिखाया जाए। उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, शनिवार को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कर लौटते वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एयरपोर्ट पर मिलने वालों में बिल्हौर विधायक राहुल काला बच्चा सोनकर भी थे। उन्होंने मुख्यमंत्री को बिल्हौर में हुई घटना के बारे में जानकारी दी। विधायक ने बताया कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आरोपितों से सख्ती से निपटा जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विधायक ने कहा कि उन्होंने इस मामले में पुलिस अधिकारियों से रासुका के तहत कार्रवाई की मांग की है। विधायक का कहना है कि यह घटना माहौल खराब करने का प्रयास किया है। लिहाजा रासुका तो लगनी ही चाहिए।

घटना के बाद देर रात पुलिस ने प्रथम सिंह की तहरीर पर बलवा, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, आकस्मिक उत्तेजना में आकर आपराधिक हमला करना, खतरनाक हथियारों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, गैर इरादतन हत्या 31 ए क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी। शनिवार सुबह धारा 308 (गैरइरादातन हत्या) को हटाकर उसकी जगह धारा 307 (जान से मारने का प्रयास) की धारा को जोड़ दिया।

सीएम से मिलने से पहले विधायक हैलट अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायल राहुल सिंह का हालचाल लिया। राहुल ने बताया कि उसके सिर का एमआरआई कराया गया है। उसकी हालत अब ठीक है। उसने विधायक को यह भी बताया कि कैसे उस पर आरोपित टूट पड़े थे, जबकि वह सिर्फ झगड़ा रोकना चाहता था। इसके बाद उन्होंने देर रात अस्पताल भेजे गए संदीप सिंह से मुलाकात की। संदीप का हाथ टूटा है और पैर में चोट आई है। हालांकि, डॉक्टरों ने उसे डिस्चार्ज कर दिया है। विधायक ने राहुल के बारे में डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने बताया कि अब उसे कोई दिक्कत नहीं है। एमआरआई और सिटी स्कैन की रिपोर्ट सामान्य आई है। एक-दो दिन में उसे भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।

कोविड को लेकर जिलास्तरीय टास्क फोर्स की बैठक संपन्न

अनुगामिनी का.सं.

पाकिम, 16 जुलाई। कोविड-19 की तैयारियों को लेकर आज जिला कलेक्टर ताशी चोफेल लेप्चा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की एक बैठक आयोजित हुई। परिस्थिति की समीक्षा, आंकलन तथा भावी तैयारियों पर चर्चा करना ही इसका उद्देश्य था। बैठक में दूसरा डोज ले चुके पात्र लोगों तथा 15 वर्ष से कम उम्र के स्कूली बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में टीके लगाने पर जोर दिया गया।

बैठक की शुरुआत में पाकिम एडीसी ने कल मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई कोविड-19 स्टेट टास्क फोर्स की बैठक के बारे में बताते हुए उपस्थित लोगों को इस वायरस का प्रसार रोकने की दिशा में उठाये गये विभिन्न कदमों के बारे में जानकारी दी। वहीं उन्होंने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के टीकाकरण पर जोर दिया और कोविड केयर सेन्टरों बनाने तथा स्कूलों में टीकाकरण कार्यक्रम चलाये जाने के बारे में भी कहा।

वहीं बैठक के दौरान क्वारंटाइन अवधि, पॉजिटिव मामलों की संख्या, प्रीकॉशन डोज के योग्य लोगों का टीकाकरण, पाकिम, रंगली तथा रेनॉक में कोविड सेन्टर की पहचान, आवश्यक उपकरण के साथ सैनीटाइजेशन टीम बनाने तथा सरकारी एवं निजी कर्मचारियों का आवश्यक तौर पर प्रीकॉशन डोज टीकाकरण करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई।

इसके अलावा इस दौरान सम्बंधित सरकारी अधिकारियों ने जिले में कोविड के फिर से महामारी के रुप में फैलने पर रोकथाम हेतु उठाये जाने वाले कदमों की जानकारी उपलब्ध करायी। वहीं पाकिम डीसी ने प्रीकॉशन डोज लेने वाले सरकारी कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखने, 14-19 वर्ष के बच्चों एवं युवाओं के टीकाकरण की स्थिति का रिकॉर्ड, इसकी निगरानी हेतु आईसीडीएस सेन्टर बनाने तथा सरकारी कर्मचारियों को प्रीकॉशन डोज देने सम्बंधी प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये।

बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ, एडीसी डेवलपमेंट, आरडीडी, सीईओ, शिक्षा विभाग, एडीएम, सभी एसडीएम, बीडीओ, रंगपो एमईओ, पाकिम डीपीओ एवं एसएचओ भी उपस्थित रहे।

आठ सालों में लाखों किसानों की आय हुई दोगुनी : नरेंद्र तोमर

नई दिल्ली, 16 जुलाई (एजेन्सी)। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को कहा कि बीते आठ साल में लाखों किसानों की आय दोगुनी हो गई है और इसका श्रेय केंद्र तथा राज्यों सरकारों, वैज्ञानिकों और कृषक समुदायों के हर ओर से किए गए प्रयासों को जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा तैयार एक ई-पुस्तिका भी तोमर ने जारी की। इस पुस्तिका में 75,000 ऐसे किसानों की सफलता की कहानियां हैं जिनकी आय बीते आठ वर्षों में दोगुनी या अधिक हो गई है। आईसीएआर ने कहा कि इन किसानों की आय में कुल वृद्धि 125.44 फीसदी से 271.69 फीसदी के बीच रही है। सरकार ने किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2016 में तय किया था।

आईसीएआर के 94वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए तोमर ने कहा, बीते आठ साल में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए हर ओर से प्रयास हुए हैं। लाखों किसानों की आय दोगुनी हुई है बल्कि अनेक किसानों की आय दोगुनी से अधिक हो गई है।''

उन्होंने बताया कि इन लाखों किसानों में से आईसीएआर ने पिछले वर्ष 75,000 किसानों की पहचान की है और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उनकी सफलता की कहानियों का दस्तावेजीकरण किया है। आईसीएआर के बयान के अनुसार सफलता की इन कहानियों के लिए 2016-17 को मापदंड वर्ष तथा 2020-21 को प्रभाव वाला वर्ष माना गया।

पटना में मटन दुकान चलाने वाले सोनू कुरैशी के हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पांच आरोपी गिरफ्तार

पटना, 16 जुलाई (का.सं.)। बिहार की राजधानी पटना में मटन दुकान चलाने वाले सोनू कुरैशी की हत्या को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। साथ ही इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वारदात के पीछे वर्चस्व का विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि हत्या में शामिल दो आरोपी एक वार्ड पार्षद के भतीजे हैं जो अभी फरार बताए जा रहे हैं। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

गौरतलब है कि शास्त्रीनगर थाने के आईजीआईएमएस के पीछे 12 जुलाई की देर रात मटन दुकान के कर्मचारी सोनू कुरैशी की हत्या की वारदात को कुल सात अपराधियों ने अंजाम दिया था। गिरफ्तार पांचों अपराधियों में समनपुरा निवासी साहिल, सन्नी, रितिक उर्फ चुन्नीलाल, अली उर्फ बंटी और रीशू कुरैशी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त खून से सने दो चाकू, दो चप्पल, एक मोबाइल फोन व आधार कार्ड बरामद किया है।

पुलिस के मुताबिक, वर्चस्व को लेकर घटना से तीन दिन पूर्व सोनू की अपराधियों का विवाद हुआ था। इसको लेकर 12 जुलाई की देर रात सोनू को मटन पार्टी के लिए आरोपियों ने आईजीआईएमएस के पीछे जंगल में बुलाया था। इन लोगों ने पहले से ही हत्या की साजिश बना रखी थी। सन्नी व बंटी उसे लेकर आये और तय साजिश के तहत चाकू से गोद-गोद कर उसकी हत्या कर दी। उसके शरीर पर चाकू के 20 से अधिक वार किए गए थे।

पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले आरोपी साहिल को पकड़ा। इसके बाद साहिल ने अपने साथ रहे अन्य के नामों की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने ठिकानों पर छापेमारी कर पांचों अपराधियों को धर-दबोचा जबकि राजू व फैज भाग निकला। शास्त्रीनगर थानाध्यक्ष रामशंकर सिंह ने बताया कि पकड़े गये सभी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और मोबाइल छिनतई व अन्य घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं।

शराब के नशे में पिता ने नाबालिग बेटी से किया दुष्कर्म, पीड़िता की हालत नाजुक

फतेहपुर, 16 जुलाई (एजेन्सी)। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में नशे की हालत में एक पिता ने अपनी 11 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपित फरार हो गया वहीं, नाजुक हालत में पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस आरोपित पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे तलाश रही है।

फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र में एक महिला शुक्रवार को अपनी दो बेटियों को घर में छोड़कर धान रोपाई के लिए गई थी। दोपहर उसकी बड़ी बेटी सो रही थी, वहीं छोटी बेटी दूसरे कमरे में खेल रही थी। तभी नशे की हालत में पिता घर आया और उसने बड़ी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के शोर मचाने पर छोटी बेटी बाहर आई। उसने पड़ोसियों को आवाज दी, जब तक लोग पहुंचे आरोपित पिता फरार हो गया। लोगों ने उसकी मां को जानकारी दी और गंभीर हालात में बेटी को सीएचसी हरदों में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची की हालत चिंताजनक है, उसे जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई है। वहीं, सीओ खागा संजय सिंह ने बताया कि आरोपित पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है।

अपने अधिकारों को .....

बोर्ड के अध्यक्ष सीके राना ने उपभोक्ता अधिकारों एवं सुविधाओं की जानकारी प्रदान करने हेतु इस तरह कार्यक्रम के आयोजन की प्रशंसा करते हुए लोगों से इसके बारे में अधिक से अधिक जागरूक होने एवं दूसरों को भी जागरूक बनाने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने अन्य सम्बंधित विभागों से भी इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करने हेतु प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सेवानिवृत्त सचिव डी. पी. शर्मा भी मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन के रूप में अतिरिक्त खाद्य व आपूर्ति सचिव श्रीमती डिकी डोमा भूटिया और एलएमयू एवं सीपी प्रकोष्ठ के उप-निदेशक तितास बसनेत शामिल हुए।

जो लोग राष्ट्रपति चुनाव में पहचान की बात कर रहे, वो आदिवासी को पीएम बना दें: यशवंत सिन्हा

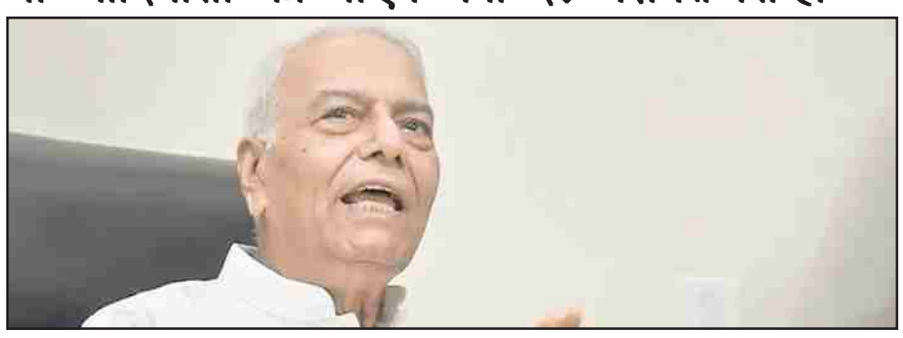

रांची, 16 जुलाई (एजेन्सी)। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा ने कहा है कि यह हमारे संविधान में इकलौता पद है, जिसका चुनाव पूरे देश के स्तर पर लड़ा जाता है। इस बार इस चुनाव ने ऐसे अभियान का रूप ले लिया है, जहां लड़ाई पहचान की नहीं बल्कि विचारधारा की हो गयी है। जो लोग आदिवासी पहचान, हित और सम्मान की बात कर रहे हैं, वह क्यों नहीं आदिवासी को प्रधानमंत्री बना देते? सिन्हा शनिवार को यहां कांग्रेस विधायकों और सांसदों से मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब थे। मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे।

सिन्हा ने कहा कि एक तरफ हमलोग लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़े हैं, वहीं दूसरी ओर खड़े लोग लोकतंत्र को खत्म करने पर तुले हैं। उन्होंने राज्य के सांसदों और विधायकों से अपील की कि जाति के आधार पर किसी का समर्थन नहीं हो, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट करें।

देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति की चर्चा करते हुए सिन्हा ने कहा कि अब प्रजातंत्र को ही खत्म करने की कोशिश चल रही है। अब तो सरकार के खिलाफ न तो संसद में बोल सकते हैं और न ही संसद के बाहर विरोध कर सकते हैं। शब्दों को असंसदीय बताते हुए जो सूची जारी की गयी है, उसका मतलब यही है कि संसद में सिर्फ सरकार का स्तुति गान करना है। ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। उन्होंने कहा कि लोकशाही का जो मंदिर है उसे खत्म किया जा रहा है। केवल पांच साल में वोट डालना ही प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र तो रोज व्यवहार में दिखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि देश में हर व्यक्ति के लिए एक तरह के डर का माहौल है,सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर यह डर उनके कैबिनेट के मंत्रियों में है, उनके अपने लोग भी डरे हुए हैं। जिस तरह से ईडी, सीबीआई और इन्कम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, उसमें सरकार के खिलाफ वही लड़ सकता है जो बेदाग है।

जब सिन्हा से यह पूछा गया कि क्या चुनाव में आपको आपके सांसद पुत्र जयंत सिन्हा का वोट मिलेगा? उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र से इस बारे में बात कर लीजिए। मुझे उसकी तरफ कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है।

49.4 करोड़ एकड़ कृषि भूमि को सिंचित किया जाए तो भारत पूरी दुनिया का भर सकता है पेट : अमित शाह

नई दिल्ली, 16 जुलाई (एजेन्सी)। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) से कहा कि सहकारिता बैंकों को केवल बैंकिंग तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि खेती के विस्तार, उपज बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि को सुगम व किसानों को समृद्ध बनाने के लिए गांव-गांव में किसानों से संवाद कर उन्हें जागरूक बनाना भी एआरडीबी की ही जिम्मेदारी है। शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी क्षेत्र का डेटाबेस बनाने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र का कोई भी एकीकृत डेटाबेस नहीं है और डेटाबेस नहीं होने पर क्षेत्र के विस्तार के बारे में नहीं सोचा जा सकता है।

उन्होंने कहा, विस्तार तभी हो सकता है जब आप जानते हो कि विस्तार कहां करना है।''सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारी बैंकों को देश में सिंचित भूमि को बढ़ाने के उद्देश्य से कर्ज प्रदान करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, एआरडीबी सिंचाई परियोजनाओं और अन्य अवसंरचनाओं समेत कृषि क्षेत्र को लंबी अवधि के और कर्ज देने पर ध्यान दें।'' शाह ने कहा कि छोटे किसानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सहकारी बैंकों को इस बारे में सोचना चाहिए कि सहकारिता की भावना के साथ इस तरह के छोटे खेतों में किस तरह काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में 49.4 करोड़ एकड़ कृषि भूमि है, जो अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। यदि पूरी कृषि भूमि को सिंचित किया जाए तो भारत पूरी दुनिया का पेट भर सकता है।

एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, यदि आप पीछे मुड़कर देखेंगे और सहकारिता संस्थानों के जरिए दीर्घकालिक ऋण की पिछले 90 वर्ष की यात्रा पर गौर करेंगे कि यह कैसे कम हुआ है तो आंकड़ों को देखने पर पाएंगे कि यह बढ़ा ही नहीं है।'' उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक ऋण में कई बाधाएं हैं और अब समय आ गया है कि सहकारिता की भावना के साथ इन अवरोधकों से पार पाया जाए। शाह ने कहा कि सहकारिता बैंकों को केवल बैंकों के तौर पर काम नहीं करना चाहिए बल्कि सिंचाई जैसी कृषि अवसंरचना की स्थापना जैसी अन्य सहकारी गतिविधियों पर भी ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने बताया कि सहकारिता मंत्रालय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को बहुआयामी बनाने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा, हमने इसके लिए आदर्श उप-नियम बनाकर प्रदेशों में चर्चा के लिए भेजे है। सहकारिता के तत्व को बढ़ाते हुए हम 70-80 साल पुराने कानूनों को बदलकर पैक्स में नई-नई गतिविधियां जोड़ने काम कर रहे है।'' शाह ने कहा, अनेक बैंकों ने नए-नए सुधार किए मगर वे सुधार बैंकों तक ही सीमित रह गए और उनका लाभ पूरे क्षेत्र को नहीं मिला। बैंक केंद्रित सुधार इस क्षेत्र को नहीं बदल सकते।

अगर क्षेत्र में सुधार आएंगे तो सहकारिता अपने आप मजबूत हो जाएगी।''उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से 70 साल में 64 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य बनी, लेकिन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 8 साल में 64 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में वृद्धि हुई और कृषि का निर्यात पहली बार 50 अरब डॉलर को पार कर गया है। शाह ने कहा कि यह किसान कल्याण के प्रति मोदी सरकार की निष्ठा को दर्शाता है।

मेधा पाटकर की मुश्किलें बढ़ीं, धोखाधड़ी मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित

बड़वानी, 16 जुलाई (एजेन्सी)। मध्य प्रदेश पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर तथा अन्य 11 लोगों के विरुद्ध कथित धोखाधड़ी के मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। इसके साथ ही आज मेधा पाटकर के बड़वानी कार्यालय में नोटिस भी तामील कराया है।

बड़वानी पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक, राजपुर के प्रीतम राज बडोले की शिकायत पर नर्मदा नव निर्माण एनजीओ से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध थाना बड़वानी में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने एसडीओपी रूपरेखा यादव के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

एसआईटी द्वारा एफआईआर में उल्लेखित नर्मदा नव निर्माण से संबंधित खातों को तस्दीक और ट्रस्ट की जानकारी हेतु महाराष्ट्र के मुंबई, नंदूरबार और धाड़गांव पहुंचकर जानकारी प्राप्त की गई।

एसआईटी टीम ने मुंबई में चैरिटी कमिश्नर ऑफिस से ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज प्राप्त करने के अलावा वहां बैंक खातों से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की। इसी तरह एक अन्य टीम ने नंदूरबार एवं धाड़गांव से ट्रस्ट से संबंधित बैंक खातों की जानकारी प्राप्त की।

इसके साथ ही शनिवार को थाना प्रभारी एसएस रघुवंशी ने ट्रस्ट के बड़वानी स्थित ऑफिस जाकर नोटिस तामील कराया और मेधा पाटकर को ट्रस्ट से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने और बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित होने को कहा है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में कानून के जानकारों से राय लेकर समीक्षा उपरांत आए साक्ष्यों के अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

एसआईटी प्रमुख रूप रेखा यादव ने बताया कि इस मामले में मेधा पाटकर समेत 12 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है तथा दो अन्य आरोपी ट्रस्ट से इस्तीफा दे चुके हैं। इस ट्रस्ट के द्वारा मध्य प्रदेश के चार अन्य व्यक्तियों को ट्रस्टी बनाया गया था, इसलिए उन्हें भी नोटिस भेजा गया है।

नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यालय पर उपस्थित कार्यकर्ता महेंद्र तोमर ने पत्रकारों को बताया कि आज बड़वानी पुलिस के नगर निरीक्षक एसएस रघुवंशी द्वारा हेराफेरी की एक शिकायत को लेकर नोटिस तामील कराया गया है। उन्होंने कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं और इस नोटिस पर हमारे ट्रस्टी तथा वकील जवाब प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि नर्मदा नव निर्माण ट्रस्ट वैधानिक रूप से संचालित है और इसके माध्यम से जीवन शालाएं भी चल रही हैं। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट का नियमानुसर प्रतिवर्ष ऑडिट होता है।

उल्लेखनीय है कि शिकायत के आधार पर 9 जुलाई को बड़वानी कोतवाली पुलिस ने नर्मदा नव निर्माण एनजीओ की मेधा पाटकर तथा अन्य 11 लोगों के विरुद्ध कथित तौर पर साढ़े 13 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। उन पर आरोप था कि ट्रस्ट द्वारा मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के आदिवासी बच्चों के विकास तथा शिक्षा के नाम पर एकत्रित किए गए धन का दुरुपयोग किया गया है। उन पर आरोप था कि उक्त धन विभिन्न आंदोलनों और देश विरोधी गतिविधियों के लिए खर्च किया गया। पाटकर ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया था।

बीजेपी हवा में महल बनाने की नायाब कला में माहिर : अखिलेश

लखनऊ, 16 जुलाई (एजेन्सी)। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तंज कसते हुए कहा कि उसे हवा में महल बनाने की नायाब कला आती है। आधे-अधूरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर जनता के साथ इस पार्टी ने राजनीतिक धोखाधड़ी की है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया और इसी को लेकर सपा नेता ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। अखिलेश ने कहा कि आधे-अधूरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जिस हड़बड़ी में किया गया है, उसे जनता के विश्वास के साथ राजनीतिक धोखाधड़ी ही कही जा सकती है। रेवड़ी बांटकर थैंक्यू का अभियान चलवाने वाले सत्ताधारी अगर युवाओं को रोजगार दें तभी वे दोषारोपण संस्कृति से बच सकते हैं।

अखिलेश ने कहा कि जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है वहां सिर्फ पिलर खड़े हैं, स्लैब अधूरी है, सरियों के ढांचे को बोल दिया एक्सप्रेसवे। अधूरी सड़कों का उद्घाटन कर जनता को भ्रमित किया गया है। न टोल तैयार, नहीं कनेक्टिंग रोड बनी। बस ऐसे ही उद्घाटन पर जनधन लुटा दिया गया। समाजवादी सरकार में डिजाइन हुए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तब हवाई पट्टी बनी। वहां वायु सेना के विमान भी उतारे जा सके। लेकिन बुंदेलखंड की डिजाइन ऐसे ही चलताऊ बनी है तभी डिफेंस कॉरिडोर के पास होने के बाद भी यहां भाजपा सरकार समाजवादी सरकार के समय बनी एक्सप्रेसवे जैसी हवाई पट्टी तक नहीं बना पाई। भाजपा का अधूरा एक्सप्रेसवे चित्रकूट तक भी नहीं पहुंच पाया।

सपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि भाजपा सरकार ने अपनी वाहवाही के लिए आधे-अधूरे एक्सप्रेसवे का लोकार्पण तो करा लिया किंतु उसके आसपास बुनियादी सुविधाओं तक की व्यवस्था नहीं की गई। किसानों के लिए मंडी नहीं बनाई गई। किसान हितैषी का झूठा तमगा लगाकर भाजपा सरकार ने वस्तुत: किसानों को धोखा देने का रिकॉर्ड दोहराया है। जब वहां निवेश नहीं आया और उद्योग नहीं लगे तो नौजवानों को रोजगार कहां मिलेगा?

अखिलेश ने दावा कि किया सच तो यह है कि एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं को बनाने का श्रेय समाजवादी सरकार को जाता है। एक्सप्रेसवे बनाने के लिए भाजपा नेतृत्व समाजवादी पार्टी सरकार की नकल तो कर सकता हैं पर उस जैसी गुणवत्ता नहीं दे सकता है। भाजपा का खोखला विकास कार्यक्रम बुंदेलखंड में अच्छे दिन आने की तनिक भी संभावना नहीं जगाता है। यहां किसान, नौजवान बदहाली में जी रहे हैं। जल संकट के साथ शिक्षा-स्वास्थ्य के क्षेत्र में घोर उपेक्षा बरती जा रही है।

अखिलेश ने कहा कि यह समाजवादी सरकार ही थी जिसने बुंदेलखंड में विकास की वास्तविक नींव रखी थी। चरखारी में सात सरोवरों के जीर्णोद्धार के साथ उनका सौंदर्यीकरण कराया था। वृहद वृक्षारोपण का रिकॉर्ड कायम किया गया। रोटी-रोजगार की नई व्यवस्थाएं की। किसानों, गरीबों और नौजवानों के लिए विशेष योजनाएं शुरू की थीं। भाजपा सरकार ने आते ही जनहित को तिलांजलि देने और समाजवादी सरकार की योजनाओं को बर्बाद करने का काम किया है।

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 08:00 PM
DEAR OSTRICH EVENING
SATURDAY WEEKLY LOTTERY
Draw No:185 DrawDate on:16/07/22
1st Prize ₹1 Crore/- 40J 42096
(Including Super Prize Amt)
Cons. Prize ₹1000/- 42096 (REMAINING ALL SERIALS)
2nd Prize ₹9000/-
06755 14630 42886 53839 73253 78091 82565 87461 88699 90573
3rd Prize ₹450/-
0941 0982 1693 1946 5534 6656 7043 8068 8412 9450
4th Prize ₹250/-
1875 2314 3216 3865 4454 5729 7697 8439 9092 9825
5th Prize ₹120/-
0041 0120 0217 0237 0317 0408 0422 0438 0527 0698
1016 1056 1072 1199 1200 1253 1633 1919 2034 2139
2427 2445 2549 2742 2766 2913 2951 3057 3098 3109
3367 3484 3491 3680 3803 3876 3916 4032 4351 4369
4457 4513 4611 4765 4793 4824 4951 5228 5242 5269
5278 5341 5532 5651 5653 5680 5697 5712 5855 5924
6012 6073 6234 6318 6413 6558 6729 6765 6899 6900
6980 7017 7111 7119 7136 7143 7185 7284 7448 7535
7564 7582 7800 7806 7866 8175 8649 8689 8710 8779
8874 8901 8950 8987 9183 9245 9277 9427 9584 9972
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 06:00 PM
DEAR MARS SATURDAY
WEEKLY LOTTERY
Draw No:85 DrawDate on:16/07/22
1st Prize ₹1 Crore/- 85H 55090
(Including Super Prize Amt)
Cons. Prize ₹1000/- 55090 (REMAINING ALL SERIALS)
2nd Prize ₹9000/-
05122 15263 25900 45039 59400 70097 73048 90554 99391 99973
3rd Prize ₹450/-
0073 0334 1390 7051 7252 7536 7869 7877 8713 9697
4th Prize ₹250/-
0363 0582 1060 1383 2055 3409 5589 6244 7055 7455
5th Prize ₹120/-
0115 0116 0135 0306 0339 0353 0578 0594 0874 0951
1071 1074 1110 1221 1408 1542 1774 1947 2090 2366
2530 2535 2654 2941 3416 3420 3432 3441 3482 3557
3616 3696 3808 3819 3951 3969 3987 4001 4145 4229
4304 4316 4448 4574 4646 4682 5049 5142 5347 5356
5464 5658 5682 5699 5871 5884 6017 6197 6214 6218
6224 6236 6245 6262 6329 6449 6808 6875 6939 7007
7322 7519 7596 7644 7649 7653 7664 7668 7702 7858
7951 8031 8122 8156 8187 8219 8230 8264 8415 8604
8963 9026 9237 9309 9355 9475 9546 9897 9956 9974
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES
Draw Time: 01:00 PM
DEAR KOSAI MORNING
SATURDAY WEEKLY LOTTERY
Draw No:85 DrawDate on:16/07/22
1st Prize ₹1 Crore/- 96L 46184
(Including Super Prize Amt)
Cons. Prize ₹1000/- 46184 (REMAINING ALL SERIALS)
2nd Prize ₹9000/-
02962 03783 06150 37802 38584 66437 72063 87305 89411 90446
3rd Prize ₹450/-
0399 1021 1563 2049 2448 6119 6337 6987 8766 8969
4th Prize ₹250/-
0219 1214 1577 2039 2149 3090 4431 6996 7338 9684
5th Prize ₹120/-
0058 0074 0117 0215 0572 0597 0657 0792 0822 0980
1043 1124 1126 1208 1240 1243 1339 1388 1528 1628
1657 1703 1714 1740 1771 1920 2025 2038 2142 2145
2169 2354 2574 2595 2719 2768 2798 2814 2987 3037
3126 3134 3304 3424 3489 3550 3634 3678 3733 3742
3767 3807 3894 4028 4272 4333 4370 4483 4740 4778
4940 4976 5340 5432 5612 5640 5888 5902 6027 6041
6107 6121 6336 6454 6505 6603 6643 6954 7067 7156
7356 7490 8047 8117 8202 8264 8323 8441 8587 8683
8828 9197 9223 9278 9408 9516 9560 9580 9736 9788
ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

संपादकीय पृष्ठ

भटकी हुई बहस

लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी असंसदीय शब्दों की ताजा सूची को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि यह उसकी आवाज दबाने की सरकार की ओर से की गई एक और कोशिश है। लेकिन इस संबंध में पहली बात ध्यान देने लायक यह है कि यह कोई ऐसी नई या अनोखी बात नहीं है, जो मौजूदा सरकार के कार्यकाल में की गई हो। यह 1950 से चली आ रही एक नियमित कवायद है। समय-समय पर लोकसभा सचिवालय की ओर से ऐसे शब्दों का संग्रह प्रकाशित किया जाता है, जो भारत और राष्ट्रमंडल देशों में संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही के दौरान पीठासीन अधिकारियों द्वारा असंसदीय करार दिए गए हों। यह सूची अमूमन रेफरेंस का ही काम करती है क्योंकि अंतत: संसद में किसी सदस्य के भाषण के दौरान इस्तेमाल किया गया कोई शब्द असंसदीय है या नहीं, यह पीठासीन अधिकारी ही तय करते हैं। फिर यह बात भी है कि संबंधित सूची या संग्रह में आए शब्द प्रतिबंधित नहीं हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने भी साफ किया है कि किसी भी शब्द को बैन नहीं किया गया है। जाहिर है, ऐसे में विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप उपयुक्त नहीं माना जा सकता। मगर यह उम्मीद जरूर रहेगी कि संसद की कार्यवाही के दौरान पीठासीन अधिकारी किसी शब्द या वाक्यांश को असंसदीय करार देते हुए किताबी रवैया नहीं अपनाएंगे।

संसदीय बहसों में भी वह जीवंतता दिखनी चाहिए, जो किसी लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उनके समर्थक समूहों के जिंदा होने की गारंटी मानी जाती है। इसी बिंदु पर सांसदों के लिए भी यह बात याद रखने की है कि ज्यादा कड़े या भारी लगने वाले शब्द हमेशा उनके भाषण को ज्यादा वजनदार या प्रभावी नहीं बनाते। थोड़ी सनसनी फैला देने या पांच मिनट के लिए टीवी कवरेज में आ जाने से सांसद के रूप में उनकी भूमिका ज्यादा यादगार नहीं बनती। संसद का मूल काम कानून बनाना है। किसी संसद की सफलता-असफलता अंतत: बहस और कानून की क्वॉलिटी से ही तय होती है। अफसोस की बात है कि आजकल सत्र को अधिकाधिक हंगामेदार बनाने या उसमें ज्यादा से ज्यादा विधेयक पारित करा लेने की परस्पर विरोधी रणनीतियों के बीच संसद का यह मूल काम ही उपेक्षित होता दिख रहा है।

दिलचस्प है कि संसद के पिछले कुछ सत्र खासा प्रोडक्टिव माने गए, कुछ मामलों में तो यह प्रोडक्टिविटी 100 फीसदी से भी ज्यादा बताई गई, लेकिन इस दौरान पारित कई विधेयकों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे। सीजेआई एनवी रमन भी इस बात की ओर ध्यान दिला चुके हैं कि हाल में बने कुछ कानूनों से ऐसा लगता है कि उन्हें बनाते हुए सभी पहलुओं पर पर्याप्त गंभीरता से विचार-विमर्श नहीं हुआ। सांसदों को ज्यादा चिंतित इस बात पर होना चाहिए, असंसदीय शब्दों की सूची पर नहीं।

विकास की प्राथमिकता जरूरी

भारत डोगरा

आज अफ्रीका के अनेक देशों में भूख व अकाल का संकट विकट होने के समाचार मिल रहे हैं।

अत: इस स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संगठन व विश्व खाद्य कार्यक्रम ने व्यापक स्तर पर आर्थिक राहत शिविरों व खाद्य सहायता के लिए कहा है। यह जरूरी तो है, पर केवल अल्प-कालीन राहत से दीर्घकालीन स्तर पर यहां की समस्याएं नहीं सुलझेंगी। दीर्घकालीन स्तर पर समाधान के लिए जरूरी है कि विकास की सही प्राथमिकताओं को अपनाया जाए।

अफ्रीका में अधिकांश किसान छोटे किसान हैं। इन छोटे किसानों के अनेक संगठन भी आज यही मांग कर रहे हैं कि कृषि व खाद्य क्षेत्र की प्राथमिकताओं में महत्त्वपूर्ण सुधार किया जाए तभी दीर्घकालीन व टिकाऊ समाधान मिलेंगे। इन किसान संगठनों का दावा है कि पश्चिमी देशों से सहायता प्राप्त ऐसे कार्यक्रम अफ्रीका के एक बड़े भाग में चलाए गए हैं, जो बड़ी कंपनियों के बीजों, रासायनिक खाद व कीटनाशकों के प्रसार पर आधारित हैं। इन्हें अफ्रीका की हरित क्रांति के नाम पर फैलाया गया है। इसकी प्रमुख परियोजना एग्री.आर.ए. जिसे संक्षेप में आगरा भी कहा जाता है। अब तो पश्चिमी देशों के स्वतंत्र विशेषज्ञ भी इसकी भरपूर आलोचना कर रहे हैं कि इसने अफ्रीका के छोटे किसानों पर महंगी तकनीकें थोपने का कार्य किया है जो वहां की स्थितियों के अनुकूल भी नहीं है। यदि ऐसे कार्यक्रमों के लिए पश्चिमी देशों से धन आता है तो इससे कहीं अधिक धन अफ्रीकी देशों की सरकारों को सब्सिडी के नाम पर खर्च करना पड़ता है। इस तरह अफ्रीकी देशों का कृषि बजट बाहरी व्यावसायिक हितों को बढ़ाने पर खर्च होता है, जबकि टिकाऊ खेती, पर्यावरण हितों के अनुरूप खेती को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त संसाधन सरकार के पास बचते ही नहीं हैं।

बड़ी कंपनियों ने अनेक स्थानों पर बड़े क्षेत्र हथिया लिये हैं जहां केवल उस फसल की मोनोकल्चर खेती होती है, जिसकी उस कंपनी को जरूरत है। यहां पहले मजबूत जैव-विविधता वाली वह खेती किसान करते थे जो स्थानीय मिट्टी व पानी की स्थितियों के अनुकूल थी। बड़ी कंपनियों की मोनोकल्चर खेती से भूमि की उर्वरता का व जल-संसाधनों का तेजी से ह्रास होता है। इस तरह जब बड़े क्षेत्रफल पर भूमि-उपयोग बदल जाता है तो पशुपालकों के मार्ग भी अवरुद्ध हो जाते हैं। अफ्रीका में सीमित संसाधनों का उचित उपयोग करने में घुमंतू पशुपालकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने किसानों से अच्छा तालमेल मिलाया हुआ था। पर बड़ी कंपनियों की खेती में ऐसा तालमेल बन पाना संभव नहीं है। बड़े व्यावसायिक हितों के अनुकूल कृषि व विकास नीतियां जबसे अपनाई गई हैं तबसे सारण छोटे किसानों व घुमंतू पशुपालकों दोनों की कठिनाइयां बढ़ी हैं।

इससे पहले औपनिवेशिक शासन काल की भी यही कहानी थी। सबसे अधिक अत्याचार तो गुलाम व्यापार के नाम पर हुए थे। औपनिवेशिक ताकतों ने अपने संकीर्ण स्वाथरे के लिए अफ्रीकी देशों का कृत्रिम बंटवारा किया। यह करते समय पशुपालकों के मागरे व लोगों की परंपरागत लेन-देन की उपेक्षा की गई। इस तरह परंपरागत सामाजिक व आर्थिक सहयोग व ताने-बाने की जो क्षति हुई वह आज तक चल रही है। अब समय आ गया है कि अफ्रीका की विकास की प्राथमिकताओं को यहां के किसानों, पशुपालकों व अन्य, समुदायों की जरूरतों के अनुकूल बनाया जाए। इसके लिए पर्यावरण की जरूरतों व परंपरागत ज्ञान की खूबियों की सही समझ होना भी जरूरी है। परंपरागत ज्ञान की समझ से पर्यावरण व टिकाऊ आजीविका में तालमेल बनाने में मदद मिलेगी। बढ़ती भूख की समस्या के बीच यह याद दिलाना जरूरी है कि वर्ष 1971-2011 के 40 वर्षों के बीच सेहल क्षेत्र, हार्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों में लाखों लोग भुखमरी और अकाल से मारे गए हैं। विकास व पर्यावरण पर विश्व आयोग ने वर्ष 1987 में बताया था कि पिछले लगभग तीन वर्षों में अफ्रीका में अकाल व भुखमरी से लगभग दस लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। 1970 से 2022 के बाद के 52 वर्षों में किसी अन्य क्षेत्र में भूख से इतनी अधिक मौतों का कोई अन्य उदाहरण नहीं है। इससे पहले 1959-60 के आसपास चीन में बड़ी छलांग के दौर में इससे भी अधिक मौतें अकाल व भुखमरी में हुई थीं।

विश्व खाद्य संगठन व विश्व खाद्य कार्यक्रम ने वर्ष 2021 के आरंभ में रिपोर्ट तैयार की थी हंगर हॉटसपाट जिसमें विश्व में उन 20 देशों की पहचान की गई थी, जहां भूख की समस्या सबसे कम है व भविष्य में और उग्र हो सकती है। इन 20 देशों में से 12 देश अफ्रीका महाद्वीप के थे। इसके बाद के सवा वर्ष को देखें तो तबसे लेकर अब तक अत्यधिक भूख से प्रभावित अफ्रीकी देशों व क्षेत्रों की संख्या और बढ़ गई है। नाईजीरिया व केन्या की गिनती अपेक्षाकृत ठीक-ठाक आर्थिक स्थिति के देशों में होती है पर यहां के कुछ बड़े क्षेत्रों में भी भूख की समस्या काफी विकट है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार 2010-2012 के दौरान केवल एक देश सोमालिया में भुखमरी और अकाल से 2,60,000 मौतें हुई थीं।

21वीं शताब्दी में किसी एक देश में इतने कम समय में भूख से इतनी मौतें होने का कोई भी समाचार नहीं है। ऐसी आशंकाओं और डर को देखते हुए अफ्रीका में भुखमरी व अकाल से राहत के लिए प्रयासों को तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए युद्धस्तर पर कार्यक्रम तैयार करने होंगे और समझदारी से कार्यक्रमों पर अमल करना होगा। इसके साथ ही अफ्रीका में कृषि, पशुपालन व जलवायु बदलाव अनुकूलन नीतियों को बेहतर करने की बहुत जरूरत है।

विपक्ष को तोड़ने बल्कि खत्म करने की ऐसी परम्परा पहले कभी नहीं रही

नवनीत गुर्जर

तमिलनाडु से गोवा और महाराष्ट्र तक राजनीतिक उठापटक के बादल जिस तरह गरज-चमक रहे हैं, यह राजनीतिक इतिहास के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन स्वस्थ और नैतिकता की राजनीति के लिए यह सब ठीक भी नहीं है। 1986 से 1996 के दौरान दस सालों में राष्ट्र- जीवन अकल्पनीय, अविश्वसनीय और अनिश्चित रहा था। कहना कठिन था कि 20वीं सदी के अवसानकाल में जारी रहे उस बिलोने से अमृत निकलेगा या विष।

यह भी कि इसे किसी संग्राम का अंत माना जाए या आरंभ। समाज-जीवन का हर अंग तब इस आलोड़न- विलोड़न से थरथराता रहा था। इन दस सालों में आत्मघाती जातिवाद, विभाजक सम्प्रदायवाद और लज्जाहीन भ्रष्टाचार राजनीति की पहचान बन गए थे। अर्थव्यवस्था भूमण्डलीकरण के भंवर में हिचकोले खाती रही और समृद्धि, सुख-चैन, गरीब और गांव से काफी दूर चले गए थे।

बाजारीकरण, उद्योग-व्यवसाय का ही नहीं अपितु कला, मनोरंजन, मनोविनोद और साहित्य जैसे जीवन के कोमल अंगों का भी मूल मंत्र बन गया था। उदारीकरण की सद्इच्छाओं को घोटालों की बुरी नजर लग गई थी। राजनीति के शिखर-पुरुष लोगों के दिलों में नहीं बल्कि सत्ता के दलालों की काली और वकीलों की लाल डायरियों में भी जगह बनाने लगे थे।

यह सब इसलिए हुआ, क्योंकि 1986 से 1992 तक चार आम चुनावों और पांच प्रधानमंत्रियों के उत्थान-पतन के बावजूद राजनीतिक स्थिरता दूर की ही कौड़ी रही थी। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा लाकर सत्ता के प्रासाद खड़े किए गए और बहुमत की नई परिभाषाएं गढ़ी गईं। आज यहां उस दौर को याद करने का मतलब सिर्फ इतना-सा है कि राजनीतिक अस्थिरता और स्थिरता में भी प्रशासनिक ताकत के बेखौफ होने का फर्क बहुत मामूली होता है।

अस्थिरता जब होती है तो सारे तिकड़म सरकार बचाने के लिए किए जाते हैं। और जब स्थिरता रहती है तो उत्थान-पतन के तमाम रास्ते खुद को और बलशाली बनाने के लिए अपनाए जाते हैं। प्रशासन और उसके तथा उसके जैसे सभी अंग सरकार की मंशा भांप लेते हैं और वे सब के सब वही करने लगते हैं, जो सरकार चाहती है। तमिलनाडु में एमजी रामचंद्रन और जयललिता की पार्टी टूटकर बिखर गई।

गोवा में अधिकांश कांग्रेसी विधायकों ने भाजपा की राह पकड़ ली। महाराष्ट्र में शिवसेना के हाल हर कोई जानता ही है। नया मामला यह है कि सांसदों के दबाव में उद्धव सेना भी भाजपा के राष्ट्रपति प्रत्याशी का साथ देने पर राजी हो चुकी है। अब जिसके हाथ से पार्षद तक खिसकने लगें, वह सांसदों का दबाव न माने तो क्या करे! उधर उत्तराखंड में भी कुछ उल्ट-पुल्ट ही चल रहा है।

सुना है वहां भी विपक्ष के नेता से बलशाली पार्टी की गुपचुप बातचीत चल रही है। विधायकों को तोड़ने का सीधा-सा मतलब राष्ट्रपति चुनाव में ज्यादा से ज्यादा बहुमत जुटाना है। विपक्ष को तोड़ने बल्कि खत्म करने की ऐसी परम्परा इस दौर के सिवाय पहले कभी नहीं रही। हो सकता है यह वक्त की जरूरत हो और आगे जो भी सत्ता में आए, यही सबकुछ मिसाल के तौर पर याद भी किया जाए, लेकिन किसी भी हाल में इसे स्वस्थ राजनीति के पलड़े में तो नहीं ही रखा जा सकता।

सवाल उन जनप्रतिनिधियों का भी है, जो एक के बाद एक पाला बदलते जाते हैं और उनका पार्टी-व्हिप या मर्यादा या मानस उन्हें किसी मोड़ पर भी ऐसा करने से रोकता-टोकता नहीं। हो सकता है राजनीति इसे ही कहा जाता हो!

विकास के रास्ते पर यूपी

टीवी मोहनदास

अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा वापसी की है। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने कानून-व्यवस्था की स्थापना, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा और पूरे राज्य में बुनियादी ढांचों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। एक्सप्रेस-वे और अन्य विकास कार्य राज्य की औद्योगिक विरासत को फिर से हासिल करने के एजेंडे को बढ़ावा देंगे। योगी ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत धमाकेदार ढंग से की है और वर्ष 2027 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को दस खरब डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

केंद्र सरकार ने ठीक ही माना है कि उत्तर प्रदेश का विकास देश के विकास को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि राज्य में राष्ट्र की 16 फीसदी आबादी रहती है। विगत जून में प्रधानमंत्री मोदी ने 80,000 करोड़ रुपये से अधिक की 1,406 परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। उत्तर प्रदेश के विकास पर केंद्र और राज्य, दोनों सरकारों के ध्यान दिए जाने से निवेशकों का आत्मविश्वास बढ़ा है। वित्त वर्ष 2022 में राज्य का निर्यात करीब 30 फीसदी बढ़ गया है। दूसरे चरण में राज्य इसमें तेजी ला सकता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास रणनीतियों को अपना सकता है। ज्ञान-अर्थव्यवस्था में मौजूदा और भावी सामाजिक-आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए मानव पूंजी का विकास बेहद महत्वपूर्ण है।

उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन विशाल आबादी के चलते युवा पीढ़ी के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए विशेष नीतियों की जरूरत है। राज्य सरकार ने 2022-23 शैक्षणिक सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में 6 से 14 साल के बीच के दो करोड़ बच्चों को दाखिला दिलाने का लक्ष्य रखा था। जून 2022 तक, राज्य सरकार अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि इसने 1.88 करोड़ बच्चों को सफलतापूर्वक नामांकित किया है, जो पूरे प्रदेश के 1.3 लाख स्कूलों में पढ़ रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में शैक्षिक उपलब्धियों ने सीखने की गुणवत्ता में सुधार किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में दिए गए दूरगामी सुझावों के त्वरित कार्यान्वयन के साथ, सार्वजनिक और निजी, दोनों स्कूलों के विकास को सक्षम बनाने के लिए राज्य में स्कूल नीति को संतुलित किया जाना चाहिए। विविध प्रकार के कार्यबल तैयार करने के लिए कौशल और व्यावसायिक कार्यक्रमों और 12वीं के बाद उच्च शिक्षा जैसे विभिन्न विकल्पों के साथ मानव पूंजी विकास में सुधार के लिए अब 12वीं तक शिक्षा अनिवार्य कर दी जानी चाहिए। राज्य ने उच्च शिक्षा प्रणाली का काफी विकास किया है।

राज्य हर साल करीब 16 लाख स्नातक तैयार करता है, जिनमें से आधे से अधिक महिलाएं हैं। प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात 25.3 है, जो राष्ट्रीय औसत (27.1) के बिल्कुल करीब है और राज्य की विशाल आबादी को देखते हुए उल्लेखनीय है। उत्तर प्रदेश इस व्यापक उच्च शिक्षा प्रणाली का उपयोग सीखने के परिणामों और उद्योग के लिए तैयार स्नातकों को आगे बढ़ाने के लिए कर सकता है। राज्य को हर साल इन स्नातकों के लिए रोजगार सृजन पर भी ध्यान देना चाहिए। युवा पुरुष रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश स्नातक महिलाएं ऐसा नहीं कर सकतीं, जिससे कार्यबल में राज्य की भागीदारी घटती है। महिलाओं के बीच भारत के कम एलएफपीआर (श्रमबल भागीदारी दर) का एक प्रमुख कारण उत्तर प्रदेश में महिलाओं की उच्च स्नातक दर और उनके लिए व्हाइट कॉलर जॉब की न्यूनतम संभावनाएं हैं। राज्य में योग्य नौकरियों के सृजन से कार्यबल में बड़े पैमाने पर इस मानव पूंजी को शामिल करने में मदद मिलेगी।

बुनियादी ढांचे के विकास के साथ उत्तर प्रदेश पूरे क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास को चलाने के लिए चीनी मॉडल का अनुसरण कर सकता है। इससे निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में तैयार पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और गंगा एक्सप्रेस-वे (जिस पर काम चल रहा है) और मौजूदा व्यापक सड़क नेटवर्क-सभी सही दिशा में हैं। नया जेवर हवाई अड्डा एक बार पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद राज्य और क्षेत्र यात्रियों और मालवाहक विमानों, दोनों के लिए एक वैश्विक केंद्र में तब्दील हो जाएगा। सफाई परियोजनाओं के साथ गंगा नदी को केंद्रीय जलमार्ग के रूप में विकसित किया जा सकता है।

राज्य में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है। अधिक मेडिकल कॉलेज आने से नागरिकों को आपात चिकित्सा के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश भारतीय सभ्यता का उद्गम और असंख्य विरासत स्थलों वाला राज्य है। मथुरा, अयोध्या और वाराणसी को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा होने पर इस क्षेत्र को भारी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि यह वैश्विक स्तर पर 1.2 अरब हिंदू श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। श्रम प्रधान उद्योगों में कपड़ा क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। वित्त वर्ष 2022 के आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश से निर्यात होने वाले सामान में कपड़ा/परिधान की हिस्सेदारी नौ फीसदी यानी 12,996 करोड़ रुपये थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल उत्पादों के बाद, राज्य से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की सूची में परिधान तीसरे स्थान पर हैं।

इस बीच, नोएडा भारत का सबसे प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक निर्यात केंद्र बन रहा है। श्रम प्रधान उद्योगों को घरेलू उपयोग एवं निर्यात के लिए बड़े पैमाने पर उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण की आवश्यकता होती है, और यह विशिष्ट उद्योगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया कराता है। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश को गहन शोध, बौद्धिक संपदा सृजन और उत्कृष्टता केंद्रों, अनुदान, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं तथा विनिर्माण सुविधाओं के साथ विशिष्ट कार्यबल तैयार करने के लिए निवेश खातिर अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये का निवेश पूल बनाना होगा। इस निवेश से अगले दशक में बड़े पैमाने पर उत्पादन और विकास होगा। राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के करीब विशिष्ट औद्योगिक आधार तैयार कर सकता है और वहां उपलब्ध बेहतर बुनियादी ढांचे और मानव पूंजी का लाभ उठा सकता है।

लगता नहीं कोई मोदी को चुनौती दे पाएगा

राजदीप सरदेसाई

क्या 2024 के आम चुनावों का फैसला पहले ही हो चुका है? अगर इस प्रश्न का निहितार्थ यह है कि देश के चुनावी लोकतंत्र में एक पार्टी का आधिपत्य स्थापित हो चुका है तो हमें इसका जवाब हां में देना होगा। हाल में हुई राजनीतिक घटनाएं भी यही बताती हैं कि मोदी-फाइड भाजपा विजयरथ पर सवार है, जबकि विपक्ष छिन्न-भिन्न हो चुका है।

महाराष्ट्र में जिस तरह से सत्ता पलटी, वह इस बात का एक नाटकीय उदाहरण है कि भाजपा 2024 के लिए किस तरह से कमर कस चुकी है। यूपी के बाद महाराष्ट्र ही लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद भेजने वाला राज्य है और उसे हथियाकर भाजपा ने विपक्ष के उस महत्वपूर्ण किले में सेंध लगा दी है, जिसके बलबूते वह 2024 में भाजपा को चुनौती देने का अरमान संजो सकता था।

शिवसेना का जिस तरह से विघटन हुआ, उसके मूल में पार्टी के भीतर सत्ता का संघर्ष ही नहीं था। वह एक तख्तापलट था, जिसके शिल्पकार दिल्ली में बैठे भाजपा के कर्णधार थे। जिस नि:संकोच तरीके से राज्यसत्ता का इस्तेमाल करते हुए- जिसमें केंद्रीय एजेंसियों से लेकर गुजरात और असम की पुलिस-मशीनरी और मुम्बई का राजभवन तक सब सम्मिलित थे- यह तख्तापलट किया गया, उसने देश के हर विपक्ष-शासित राज्य को चेतावनी दे डाली है।

यह भी संयोग है कि जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बोरिया-बिस्तर बांध रही थी, तब भाजपा हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक आयोजित कर रही थी। तेलंगाना में अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं और यह साफ है कि अब वह भाजपा के रडार पर है। बैठक में जिस तरह से के. चंद्रशेखर राव और उनके परिवार पर खुलकर हमला बोला गया, उससे यह भी संकेत मिला है कि भाजपा तेलंगाना में अपना सुपरिचित पार्टी बनाम परिवार वाला नैरेटिव चलाने वाली है।

हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर भाजपा तेलंगाना सहित दूसरे राज्यों में भी किसी एकनाथ शिंदे को खोज निकाले, जो अपनी पार्टी की नीतियों से नाराज हो और जिसके बहाने भाजपा जमीनी नेता बनाम वंशवाद का कार्ड खेलते हुए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। यह भी साफ है कि अब भाजपा दक्षिण के राज्यों पर नजर जमाए हुए है। 2019 के आम चुनावों में भाजपा ने 303 सीटें जीती थीं, लेकिन इनमें से केवल 29 दक्षिण से थीं। इनमें भी 25 तो अकेले कर्नाटक से थीं।

अब पार्टी की कोशिश है कि दक्षिण में अपने अस्तित्व को बढ़ाया जाए। इस तरह के प्रयासों के नतीजे रातोंरात नहीं आते, लेकिन भाजपा उत्तर भारत की हिंदी पट्टी पर अपना आधिपत्य इतनी सम्पूर्णता से स्थापित कर चुकी है कि अब वह आराम से दक्षिण के बारे में सोचने का समय निकाल सकती है। भाजपा अपना सामाजिक आधार भी बढ़ाना चाहती है।

एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की आदिवासी हैं। उनका चयन सोची-समझी रणनीति के तहत किया गया है। 2019 में भाजपा ने अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर 40 प्रतिशत का वोट-शेयर हासिल किया था। वास्तव में उसका प्रदर्शन शहरी क्षेत्रों के बजाय ग्रामीण इलाकों में कहीं बेहतर रहा था। वैसा उसने ओबीसी-एससी-एसटी वोटों को अपने पक्ष में लामबंद करके किया था, जो कि उसके परम्परागत ब्राह्मण-बनिया वोटबैंक से भी ज्यादा प्रभावी साबित हुआ था।

यहां यह भी दिलचस्प है कि भाजपा ने हाल ही में यूपी के रामपुर और आजमगढ़ में हुए लोकसभा उपचुनाव भी जीत लिए, जहां बड़ी मुस्लिम आबादी है। यह कहना तो अतिशयोक्ति होगी कि भाजपा को बड़ी तादाद में मुस्लिमों के वोट मिले होंगे, लेकिन जीत ने यह साबित कर दिया कि भाजपा इस सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश में पूर्ण वर्चस्व स्थापित कर चुकी है।

करीना कपूर के लिए शेफ बने सैफ अली खान

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान इन दिनों खाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल करीना कपूर खान की एक दोस्त अलेग्जेंड्रा गैलिगनने ने सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें सैफ किचन में कुकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं करीना अपने दोस्तों के साथ घूमती हुई नजर आ रही हैं। अलेग्जेंड्रा ने सैफ की फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'परफेक्ट संडे शेफ अली खान के साथ, जो किचन में हमारे लिए तूफान बना रहे हैं।' इसके अलावा एक फोटो में करीना और सैफ अपने कुछ और दोस्तों के साथ डाइनिंग टेबल पर दिखाई दे रहे हैं।

सोनम कपूर की गोद भराई का फंक्शन हुआ रद्द

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर इन दिनों अपना प्रेग्नेंसी पीरियड एंजॉय कर रही हैं। सोनम और आनंद आहूजा अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सोनम कपूर के गोद भराई के फंक्शन की तैयारियां भी जोर-शोर से चल रही थी। गोद भराई के लिए सोनम बीते दिन भारत भी आ गई हैं।

लेकिन अब खबर आ रही है कि सोनम कपूर की गोद भराई का कार्यक्रम कैंसल कर दिया गया है। ये फंक्शन 17 जुलाई को मिस इंडिया कविता सिंह के घर बैंडस्टैंड, मुंबई में होने वाला था। बताया जा रहा है कि कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोनम की गोद भराई का फंक्शन कैंसल करना पड़ गया है।

अनिल कपूर ने अपनी बेटी सोनम के लिए ग्रैंड गोद भराई का फंक्शन रखा था। उन्होंने इंडस्ट्री के कुछ खास दोस्तों और परिवार के सदस्यों को निमंत्रण भी दे दिया था। लेकिन बाद में कपूर फैमिली ने होने वाली मां और उनके बच्चे के लिए किसी भी जोखिम से बचने के लिए आखिरी समय में ये फंक्शन कैंसल करने का फैसला किया।

खबरों के अनुसार सोनम कपूर बेबी शावर में डिजाइनर अबू जानी संदीप खोसला द्वारा बनाया आउटफिट पहनने वाली थीं। सोनम अपनी शादी के समय की ही तरह इस बार भी अपनी मां की जूलरी पहनतीं। वहीं सोनम के बेबी शावर पर पूजा ढिंगरा स्पेशल थीम केक तैयार करने वाली थीं।

बता दें कि सोनम कपूर और आनंद अहूजा ने एक-दूसरे को कई साल तक डेट करने के बाद 2018 में शादी रचाई थी। सोनम ने इसी साल मार्च में अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा की थी। पिछले महीने लंदन में सोनम की गोद भराई का फंक्शन काफी धूम-धाम से मनाया गया था।

फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं रणबीर कपूर

रणबीर कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'शमशेरा' के प्रमोशन में एक खुलासा किया है। एक इंटरव्यू में रणबीर ने बताया कि वो एक फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने लॉकडाउन के दौरान एक स्टोरी भी लिखी है। साथ ही एक्टर ने कहा कि इस फिल्म को आलिया भट्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं। रणबीर ने कहा, 'मैंने अनुराग बसु के साथ मिलकर जग्गा जासूस को प्रोड्यूस किया था, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने उस फिल्म को एक एक्टर के तौर पर प्रोड्यूस किया था। इसलिए अभी तक मैंने प्रोड्यूसर के तौर पर काम नहीं किया है, लेकिन हां मैं हमेशा से एक फिल्म डायरेक्ट करना चाहता हूं।' रणबीर ने बातचीत के दौरान आगे कहा, 'मैंने इस लॉकडाउन में एक स्टोरी भी लिखी है। कहानी मुझे काफी पसंद आई, लेकिन मुझे लिखना नहीं आता। इसलिए मैं अपनी स्टोरी को लोगों के साथ शेयर करुंगा और उनके साथ एक फिल्म बनाउंगा। प्रोडक्शन से ज्यादा मैं डायरेक्शन करना चाहता हूं। मेरी वाइफ एक बहुत अच्छी प्रोड्यूसर है, तो हो सकता है कि वो मेरी फिल्म प्रोड्यूस करे।'

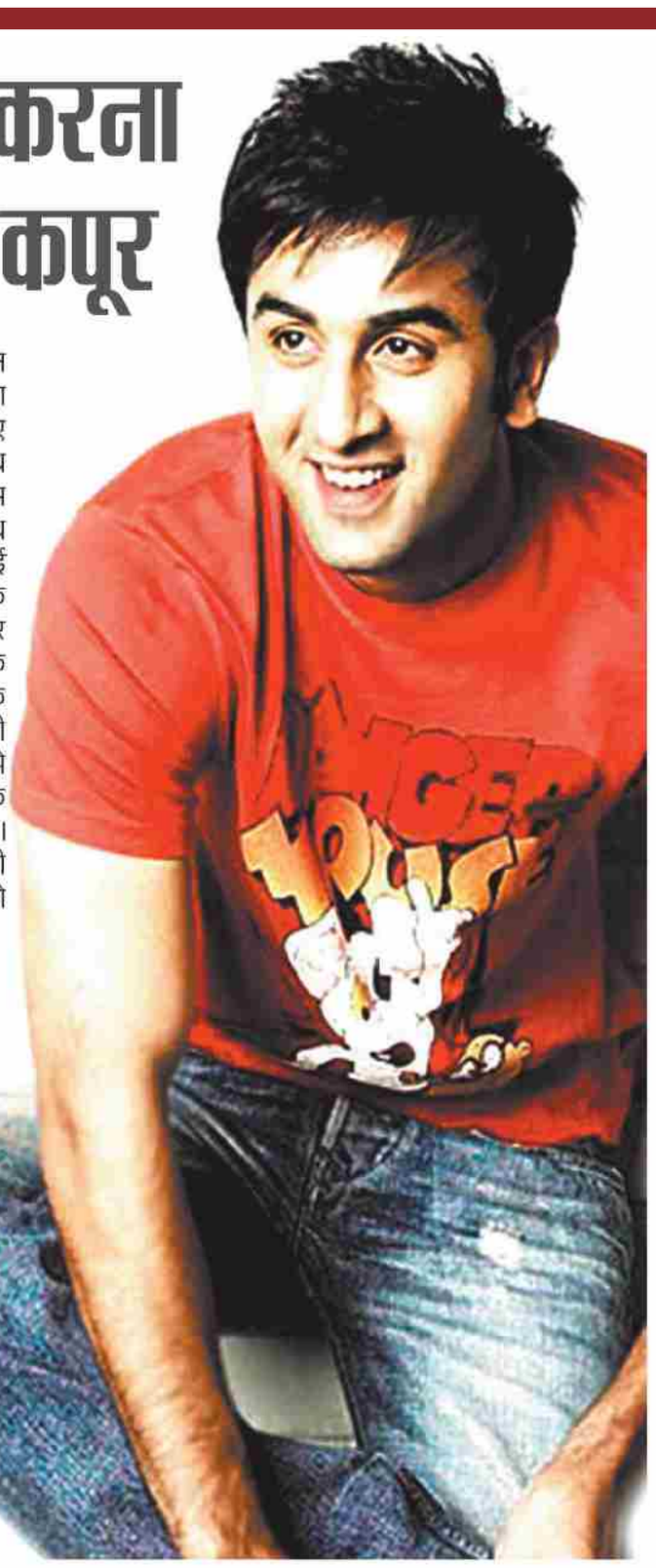

क्या जुड़वां बच्चों की मां बनेंगी आलिया भट्ट? सोशल मीडिया पर लग रहे कयास

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने शादी के कुछ महीनों बाद ही प्रेग्नेंसी की घोषणा कर सभी को चौंका दिया था। आलिया इन दिनों प्रेग्नेंसी पीरियड एंजॉय कर रही हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर खबर आ रही है कि आलिया जुड़वां बच्चों की मां बनेंगी। यह खबर तब शुरू हुई जब आलिया अपनी हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग खत्म करके वापस मुंबई लौटीं। इस दौरान एयरपोर्ट पर आलिया का बेबी बंप देख लोग कयास लगाने लगे कि शादी के तीन महीने के अंदर ही आलिया का इतना बड़ा बेबी बंप होने की वजह जुड़वां बच्चे भी हो सकते हैं। वहीं आलिया और रणबीर की जन्म कुंडली के आधार पर एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने भी कहा था कि, आलिया और रणबीर जुड़वां बच्चों के माता-पिता बनेंगे। हालांकि इस तरह की खबरों पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। यह महज सोशल मीडिया पर चल रहे कयास है। बता दें कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर इसी साल अप्रैल में शादी के बंधन में बंधे थे। आलिया इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' के प्रमोशन में बिजी हैं। इस फिल्म में वह पहली बार अपने पति रणबीर कपूर संग पर्दे पर रोमांस करती नजर आएंगी।

निया शर्मा को मिला काम, इस रियलिटी शो में आएंगी नजर

टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा बीते काफी समय से पर्दे से गायब चल रही थीं। वहीं एक इंटरव्यू के दौरान निया ने कहा था कि वह काफी समय से वो काम की तलाश में हैं लेकिन उन्हें इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा है। वहीं अब निया शर्मा को काम मिल गया है। एक्ट्रेस पॉपुलर डांस रिएलिटी शो 'झलक दिखला जा' में नजर आएंगी। 'झलक दिखला जा' का 10वां सीजन शुरू होने जा रहा है। इस डांस रियलिटी शो को माधुरी दीक्षित, करण जौबर और नोहा फतेही जज करेंगे। वहीं इस शो के कंटेस्टेंट्स के तौर पर फिलहार तीन नाम सामने आए हैं, जिनमें से एक निया शर्मा है। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार निया शर्मा और हिना खान उन कुछ सेलिब्रिटिज की लिस्ट में शामिल हैं, जि-?हें मेकर्स ने सबसे पहले एप्रोच किया है। निया शर्मा ने शो में आने की बात कंफर्म कर दी है। वहीं हिना के साथ अभी भी बातचीत जारी है। बता दें कि निया शर्मा ने साल 2010 में टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा था। वह एक हजारों में मेरी बहना है, जमाई राजा, इश्क में मरजावां और नागिन 4 जैसे कई शोज में नजर आ चुकी हैं। निया पिछले 2 साल से पर्दे से गायब हैं।

दिल्ली में सुरक्षित महसूस नहीं करती सान्या

दिल्ली की रहने वाली एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा ने राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात की है। सान्या इस समय मुंबई में हैं और दिल्ली के बजाय वे वहां रहना ही पसंद करती हैं। हाल ही में अपने गृहनगर को असुरक्षित बताते हुए सान्या मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में ज्यादातर महिलाओं को सुरक्षा के मुद्दों का सामना करना पड़ता है। मुंबई और दिल्ली दोनों शहरों में अपने रहने के अनुभव के बारे में सान्या मल्होत्रा ने बताया, 'मैं दिल्ली से हूं और एक बहुत अच्छा कारण है कि मैं मुंबई को दिल्ली से ज्यादा पसंद करती हूं। मैं मुंबई में ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हूं। मुझे नहीं पता कि दिल्ली में सुधार हुआ है या नहीं, लेकिन मैं वहां सुरक्षित महसूस नहीं करती हूं। मैं इसका कोई कारण भी नहीं बता सकती। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में एक भी ऐसी महिला होगी, जिसने छेड़खानी का सामना नहीं किया हो।'

बिहारी सीखते नजर आए ऋतिक रोशन

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक्टर बिहारी एक्सेंट में अपनी 'सिचुएसन' समझाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल 2019 में ऋतिक की फिल्म 'सुपर 30' रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने मैथ्स टीचर आनंद कुमार का रोल प्ले किया था। आनंद बिहार से हैं, इसलिए ऋतिक ने उनके बिहारी बोलने के लहजे को भी कॉपी कर लिया था। वहीं एक्टर को ऐसे बिहारी बोलते देख सबकी हंसी छूट जाती है। बता दें आनंद एक मैथेमेटिशियन हैं, जो बिहार में गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लासेस चलाते हैं।

इवाना ट्रंप की मौत दुर्घटनावश हुई, न्यूयॉर्क के चिकित्सा परीक्षक ने किया खुलासा

न्यूयॉर्क। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी इवाना ट्रंप की मृत्यु शरीर पर चोट लगने के कारण दुर्घटनावश हुई। न्यूयॉर्क शहर के चिकित्सा परीक्षक के कार्यालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया था कि पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या उनकी मौत सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। चिकित्सा परीक्षक की संक्षिप्त रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि यह दुर्घटना कब हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार को बताया था कि इवाना का मैनहट्टन के अपर ईस्ट साइड में सेंट्रल पार्क के समीप उनके घर में निधन हो गया। वह 73 वर्ष की थीं। ट्रंप दंपती 1980 के दौर में न्यूयॉर्क के प्रभावशाली दंपती थे। हालांकि, बाद में दोनों ने तलाक ले लिया था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मार्ला मैपल्स से शादी कर ली थी। हाल के वर्षों में इवाना ट्रंप के अपने पूर्व पति से संबंध अच्छे हो गए थे। उन्होंने 2017 में आयी एक किताब में लिखा था कि वे हफ्ते में एक बार बात जरूर करते हैं। इवाना ने 2016 में 'न्यूयॉर्क पोस्ट' से कहा था कि वह पूर्व राष्ट्रपति की समर्थक और सलाहकार दोनों हैं। इवाना का जन्म चेक गणराज्य के चेकोस्लोवाक शहर में 1949 में हुआ था। उन्होंने ट्रंप से 1977 में शादी की थी।

पाकिस्तान के सिंध में युवक की हत्या के बाद झड़प, 160 लोग गिरफ्तार

कराची। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधियों और पश्तूनों के बीच झड़प होने के बाद करीब 160 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद के एक होटल में एक सिंधी व्यक्ति की हत्या के बाद दोनों समुदायों के बीच झड़प हुई। सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि बिलाल काका (35) नामक एक व्यक्ति को एक पश्तून होटल के मालिक ने पीटा और बाद में उसकी हत्या कर दी। यह घटना मंगलवार को हैदराबाद में हुई थी। भोजन के बिल को लेकर विवाद शुरू हुआ था। मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार, काका और उसके चार दोस्तों ने होटल के मालिक शाह सरवर पठान को धमकी दी थी जिससे स्थिति बिगड़ गई। दोनों समुदायों के बीच कई स्थानों पर झड़पें हुईं।

अमेरिका में कम से कम 20 वाहनों के आपस में टकराने से पांच लोगों की मौत

हार्डिन (अमेरिका)। अमेरिका में मोंटाना राज्य के इंटरस्टेट 90 पर शुक्रवार शाम को कम से कम 20 वाहनों के आपस में टकरा जाने के कारण पांच लोगों की मौत हो गयी है। प्राधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। गर्वनर ग्रेग गियाफोर्ते ने ट्वीट किया, ''मैं हार्डिन के समीप बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की खबरों से बहुत दुखी हूं। कृपया मेरे साथ पीड़ितों और उनके प्रियजनों के लिए दुआ कीजिए। हम प्रथम बचावकर्ताओं की उनकी सेवा के लिए आभारी हैं।' समाचार चैनल 'केटीवीए' की खबरों के अनुसार, यह हादसा हार्डिन से पांच किलोमीटर दूर पश्चिम में हुआ। मोंटाना राजमार्ग गश्ती दल के सर्जेंट जे नेल्सन ने 'एमटीएन' न्यूज को बताया कि घटना की सूचना शाम करीब साढ़े चार बजे मिली और प्रथम बचावकर्ता 90 मिनट बाद घटनास्थल पर पहुंचे।

भारत ने नेपाल को बाढ़ राहत सामग्री सौंपी

काठमांडू। भारत ने शुक्रवार को नेपाल को बाढ़ और आपदा राहत सामग्री की खेप सौंपी। भारतीय दूतावास के बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार, नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने यहां गृह मंत्रालय के एक कार्यक्रम के दौरान नेपाल के गृह मंत्री बाल कृष्ण खंड को राहत सामग्री सौंपी। इनमें 3,000 टेंट और दस मोटर चालित नौकाएं भी शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान श्रीवास्तव ने आशा जताई कि ''राहत सामग्री की आपूर्ति से संबंधित एजेंसियों को समय पर इसका वितरण करने में मदद मिलेगी।'' गृह मंत्री खंड ने राहत सामग्री के समय पर वितरण के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया तथा भारत और नेपाल के बीच आपदा राहत से संबंधित सहयोग की सराहना की। बयान में कहा गया कि साझा इतिहास और संस्कृति वाले भारत और नेपाल विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक मुद्दों पर सहयोग करते हैं। भारतीय दूतावास के बयान में कहा गया है कि राहत सामग्री नेपाल में आपदा से निपटने में भारत के निरंतर सहयोग को दर्शाती है। बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं अक्सर नेपाल के साथ-साथ भारत को भी प्रभावित करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप जान-माल का नुकसान होता है। राजदूत ने कहा कि इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए दोनों देशों के पास वर्षों से एक समन्वय तंत्र है।

अमेरिका में गर्भपात संबंधी कानून बहाल करने को लेकर संसद के निचले सदन ने दी मंजूरी

वाशिंगटन। अमेरिका में गर्भपात संबंधी कानून बहाल करने को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कांग्रेस के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव में पेश किए गए एक विधेयक को मंजूरी मिल गई है। हालांकि, इस विधेयक के कानून बनने की संभावना कम है क्योंकि इसके लिए उच्च सदन सीनेट से भी मंजूरी चाहिए। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव में पेश किया गया विधेयक 210 के मुकाबले 219 मतों से पारित हुआ। सदन में एक और प्रस्ताव पर मतदान होना है जिसके तहत गर्भपात के लिए किसी अन्य प्रांत में जाने वाली महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। दरअसल, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रो बनाम वेड मामले से संबंधित फैसले को पलटते हुए गर्भपात कराने के महिलाओं के संवैधानिक अधिकार को निरस्त करने का फैसला सुनाया था। उसके बाद देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न प्रांतों को अपनी सुविधा के मुताबिक गर्भपात संबंधी कानून लागू करने का आदेश दिया था।

नीदरलैंड के किसान आंदोलन को कई देशों का समर्थन

- गायों की संख्या 30 फ़ीसदी घटाने का सरकारी फरमान

नीदरलैंड । नीदरलैंड सरकार ने किसानों से नाइट्रोजन उत्सर्जन कम करने के लिए कहा है। सरकार ने गायों की संख्या 30 फ़ीसदी घटाने के आदेश किसानों और पशुपालकों को दिए है।सरकार का कहना है कि कृषि से जुड़े लोगों को नाइट्रोजन उत्सर्जन कम करना होगा। नीदरलैंड सरकार ने 2030 तक नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया के उत्सर्जन को 50 से 70 फ़ीसदी कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार के इस निर्णय के विरोध में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों ने एयरपोर्ट और हाईवे को जाम कर दिया है। सुपर मार्केट की खाद्य सप्लाई को रोक दिया है। किसानों का कहना है पशुपालन से 5 पीढ़ियां पशुपालन के रोजगार से जीवनयापन करती आई हैं। सरकार नियम बनाकर किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर कर रही है। सरकार के नए कानून के विरोध में पशुपालकों और किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। नीदरलैंड में चल रहे किसान आंदोलन को इटली, स्पेन जर्मनी और पोलैंड के किसानों ने भी अपना समर्थन दिया है उल्लेखनीय है,नीदरलैंड की आबादी एक करोड़ 75 लाख है। नीदरलैंड में लगभग 16 लाख दुधारू पशु पंजीकृत है। इसमें बड़ी संख्या गायों की है। यहां के लोगों का पशुपालन और कैसी प्रमुख धंधा है नीदरलैंड सरकार ने पशुपालकों को गायों की संख्या 30 फीसदी कम करने को कहा है। जिससे वहां की गायों के जीवन पर भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है।

समझौते के तहत एक बार फिर एक-दूसरे के रॉकेट पर सवार होंगे अमेरिका और रूस के अंतरिक्ष यात्री

केप कैनेवरल, अमेरिका। अंतरिक्ष प्रोग्राम के अंतर्गत अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री घोषित एक समझौते के तहत एक बार फिर से रूसी रॉकेट पर सवार होंगे। वहीं रूसी अंतरिक्ष यात्री स्पेसएक्स के जरिये अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचेंगे। नासा और रूसी अधिकारियों के मुताबिक, समझौते के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अंतरिक्ष स्टेशन के सुचारू संचालन के लिए वहां हमेशा कम से कम एक अमेरिकी और एक रूसी अंतरिक्ष यात्री मौजूद रहें। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सितंबर में कजाकिस्तान से अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। इसी महीने, रूसी अंतरिक्ष यात्री एना किकिना फ्लोरिडा में स्पेसएक्स रॉकेट से उड़ान भरेंगी, जिसमें दो अमेरिकी और एक जापानी अंतरिक्ष यात्री भी सवार रहेंगे।

सउदी अरब के दौरे पर पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्वागत करते सउदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान।

सुप्रीम कोर्ट से इमरान को झटका, सत्ता परिवर्तन की साजिश संबंधी दावे खारिज

- खान ने अमेरिका पर स्थानीय सहयोगियों की मदद से उनकी सरकार को बदलने का आरोप लगाया था

इस्लामाबाद । पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सत्ता परिवर्तन की साजिश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के दावों को खारिज कर दिया है। खान को 10 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा दिया गया था, लेकिन उन्होंने संसद के फैसले को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। खान ने अमेरिका पर स्थानीय सहयोगियों की मदद से उनकी सरकार को बदलने का आरोप लगाया था। शीर्ष अदालत ने तीन अप्रैल को तत्कालीन डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने से संबंधित एक मामले में बृहस्पतिवार को एक विस्तृत फैसले में लिखा कि उसे सत्ता परिवर्तन के दावे के समर्थन में सबूत नहीं मिले। सूरी ने प्रस्ताव को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह विदेशी मदद से सरकार बदलने का प्रयास था। अदालत ने अपने आदेश में सूरी के फैसले को अवैध घोषित किया था और प्रस्ताव पर मतदान का आदेश दिया था। अदालत ने अपने विस्तृत फैसले में खान और उनके समर्थकों के इस दावे का समर्थन नहीं किया कि सरकार विदेशी हस्तक्षेप से बदली गई थी। अन्य बातों के अलावा, अदालत ने माना कि आरोप अस्पष्ट थे और सबूतों द्वारा समर्थित नहीं थे। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस आशय का कोई अवलोकन नहीं किया गया था कि अविश्वास प्रस्ताव (आरएनसी) विपक्षी दलों द्वारा या पाकिस्तान में व्यक्तियों द्वारा एक विदेशी राष्ट्र के साथ साजिश के तहत पेश किया गया था।

यूक्रेन के आवासीय क्षेत्र में रूस ने दागी तीन मिसाइलें, तीन बच्चों सहित 23 लोगों की मौत

कीव (एजेंसी)।

युद्धग्रस्त देश यूक्रेन रूस के हमलों को लगातार झेल रहा है और पांच महीने बाद भी यहां तबाही थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को रूसी मिसाइलों ने पूर्वी सीमा से दूर एक शहर पर हमला किया जिसमें तीन बच्चों सहित कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेनी अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। यूक्रेनी शहर विन्नित्सिया पर हुए हमले में 100 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। यह शहर कीव के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है और डोनबास में चल रही लड़ाई से काफी दूर है। बीबीसी की खबर के अनुसार तीन रूसी मिसाइलों ने एक ऑफिस ब्लॉक को निशाना बनाया और आवासीय इमारतों को भी क्षतिग्रस्त किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इसे 'खुला आतंकवाद' करार दिया है। यूक्रेन की सरकारी आपातकालीन सेवा ने कहा कि मिसाइलों ने नौ मंजिला इमारत को निशाना बनाया। शहर के बीच में स्थित आवासीय इमारतों पर भी मिसाइलें गिरीं जिनमें 370,000 लोग रहते हैं।

रूसी रक्षा मंत्रालय नागरिकों पर हमले से लगातार इनकार करता रहा है। मंत्रालय ने अभी तक इस पर टिप्पणी नहीं की है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि हमला काला सागर में एक पनडुब्बी से दागी गई कैलिबर क्रूज मिसाइल से हुआ था। यूक्रेन के गृह मंत्री ने कहा कि हमले के बाद

दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस और यूक्रेनी की सिक्योरिटी सर्विस उनसे पूछताछ कर रही हैं। एक वरिष्ठ क्षेत्रीय आपातकालीन सेवा अधिकारी ने स्थानीय टीवी को बताया कि हमले में 'संभवतः किसी के भी बचने की कोई संभावना नहीं है'। स्थानीय मीडिया से बात करते हुए जेलेंस्की ने कहा, 'हर रोज, रूस नागरिकों को मारता है, यूक्रेन के बच्चों को मारता है और नागरिकों के घरों पर मिसाइल हमले करता है जहां कोई मिलिट्री टारगेट नहीं है। अगर यह खुला आतंकवाद नहीं है तो क्या है?' यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि हमले में मरने वाले तीन बच्चों में से एक लिजा नाम की लड़की थी, जो रॉकेट हमले के समय अपनी मां के साथ स्पीच थैरेपी सेशन से लौट रही थी। रूसी हमलों का केंद्र अब कीव के बजाय डोनबास है जिस पर पुतिन कब्जा करना चाहते हैं। सेवेरोडोनेत्स्क और खेरसॉन जैसे शहरों पर रूस पहले ही कब्जा कर चुका है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि वह शहरों को वापस अपने नियंत्रण में लेने के लिए एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। खबरों की मानें तो जेलेंस्की ने अपने जनरलों से अभियान के लिए आवश्यक सैन्य उपकरणों की सूची बनाने के लिए कहा है।

श्रीलंका में संविधान का सम्मान करते हुए सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण हो : संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र। (एजेंसी)।

श्रीलंका में संयुक्त राष्ट्र ने देश के सभी हितधारकों से संविधान के प्रति पूर्ण सम्मान दिखाते हुए सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित करने की अपील की है। विश्व संस्था ने यह भी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि मौजूदा अस्थिरता और लोगों की शिकायतों के मूल कारण का समाधान किया जाए। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाददेश में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर हाना सिंगर-हम्दी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि यह जरूरी है कि सत्ता का हस्तांतरण संसद के भीतर और बाहर व्यापक एवं समावेशी विचार-विमर्श के साथ हो। उन्होंने कहा, ''श्रीलंका में संयुक्त राष्ट्र सभी हितधारकों से संविधान का पूर्ण सम्मान करते हुए सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण को सुनिश्चित करने का आग्रह करता है। यह महत्वपूर्ण है कि मौजूदा अस्थिरता के मूल कारणों और लोगों की शिकायतों का समाधान किया जाए। सभी हितधारकों के साथ बातचीत सभी श्रीलंकाई लोगों की चिंताओं को दूर करने और आकांक्षाओं को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है। गायिका-हम्दी ने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सुरक्षा बल संयम बरतें और मानवाधिकार सिद्धांतों और मानकों का सख्ती से पालन करें। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र तत्काल और दीर्घकालिक दोनों जरूरतों को पूरा करने के लिए श्रीलंका की सरकार और लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। रानिल विक्रमसिंघे ने शुक्रवार को श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। संसद जब तक गोटबाया राजपक्षे के उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं कर लेती, तब तक विक्रमसिंघे देश के अंतरिम राष्ट्रपति रहेंगे। गोटबाया राजपक्षे ने उनकी सरकार पर अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने और देश को दिवालिया करने के आरोप लगने के बाद इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि 73 वर्षीय विक्रमसिंघे ने प्रधान न्यायाधीश जयंत जयसूर्या के समक्ष श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।

श्रीलंका की संसद 1978 के बाद पहली बार अगले राष्ट्रपति का करेगी चुनाव, जनता नहीं करेगी वोट

कोलंबो। (एजेंसी)।

श्रीलंका में जारी उथल-पुथल के बीच गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे के मद्देनजर 1978 के बाद पहली बार देश के अगले राष्ट्रपति का चुनाव जनता के वोट के माध्यम से नहीं, बल्कि सांसदों के गुप्त मतदान से होगा। स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने ने शुक्रवार को कहा कि 225 सदस्यीय संसद 20 जुलाई को गुप्त मतदान से नए राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। श्रीलंका में 1978 के बाद से कभी भी संसद ने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान नहीं किया। वर्ष 1982, 1988, 1994, 1999, 2005, 2010, 2015 और 2019 में जनता के वोट से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। केवल एक बार 1993 में राष्ट्रपति पद मध्यावधि में खाली हुआ था, जब राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदासा की हत्या कर दी गई थी। प्रेमदासा के बचे कार्यकाल के लिए संसद द्वारा डी बी विजेतुंगा को सर्वसम्मति से चुना गया था। नए राष्ट्रपति नवंबर 2024 तक गोटबाया राजपक्षे के शेष कार्यकाल तक पद पर रहेंगे। अगले हफ्ते के मुकाबले में रानिल विक्रमसिंघे (73) दौड़ में सबसे आगे होंगे। देश में अभूतपूर्व आर्थिक संकट के बीच विक्रमसिंघे मई में प्रधानमंत्री बने। विक्रमसिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) 2020 के संसदीय चुनाव में हार गई थी। विक्रमसिंघे 1977 के बाद पहली बार कोई सीट जीतने में असफल रहे। उन्होंने एकीकृत राष्ट्रीय वोट के आधार पर आवंटित पार्टी की एकमात्र सीट के जरिए 2021 के अंत में संसद में प्रवेश किया। राष्ट्रपति पद के लिए अगले मुख्य दावेदार मुख्य विपक्षी नेता सजिथ प्रेमदासा (55) हो सकते हैं।

भारत को राहत, रूस से खरीद सकेगा एस-400, काट्सा से छूट वाला बिल पास

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

भारत के लिए अच्छी खबर है अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने भारत को रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए सीएएटीएसए प्रतिबंधों से खास छूट दिलाने वाले एक संशोधित विधेयक को गुरुवार को पारित कर दिया। भारतीय-अमेरिकी सांसद रो खन्ना द्वारा पेश किए गए इस संशोधित विधेयक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से भारत को चीन जैसे आक्रामक रुख वाले देश को रोकने में मदद करने के लिए 'काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शंस एक्ट' (सीएएटीएसए) से छूट दिलाने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया गया है। राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकार कानून (एनडीएए) पर सदन में चर्चा के दौरान गुरुवार को ध्वनि मत से यह संशोधित विधेयक पारित कर दिया गया।

खन्ना ने कहा, 'अमेरिका को चीन के बढ़ते आक्रामक रूख के मद्देनजर भारत के साथ खड़ा रहना चाहिए। भारत कॉकस के उपाध्यक्ष के तौर पर मैं हमारे देशों के बीच भागीदारी को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने पर काम कर रहा हूं कि भारतीय-चीन सीमा पर भारत अपनी रक्षा कर सकें।' उन्होंने कहा, 'यह संशोधन अत्यधिक महत्वपूर्ण है और मुझे यह देखकर गर्व हुआ कि इसे दोनों दलों के समर्थन से पारित किया गया है।' सदन में अपनी टिप्पणियों में खन्ना ने कहा कि अमेरिका-भारत भागीदारी से ज्यादा महत्वपूर्ण अमेरिका के रणनीतिक हित में और कुछ भी इतना जरूरी नहीं है।

विधेयक में कहा गया है कि 'यूनाइटेड स्टेट्स-इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीस' (आईसीईटी) दोनों देशों में सरकारों, शैक्षणिक समुदाय और उद्योगों के बीच करीबी साझेदारी विकसित करने के लिए एक स्वागत योग्य और आवश्यक कदम है ताकि कृत्रिम बुद्धिमता, क्वांटम कम्प्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी, एरोस्पेस और सेमीकंडक्टर विनिर्माण में नवीनतम प्रगति को अपनाया जा सकें। विधेयक कि इंजीनियर और कम्प्यूटर वैज्ञानिकों के बीच ऐसी भागीदारी यह सुनिश्चित करने में अहम है कि अमेरिका और भारत के साथ ही दुनियाभर में अन्य लोकतांत्रिक देश नवोन्मेष और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दे सकें, ताकि ये रूस और चीन की प्रौद्योगिकी को पछाड़ सकें। वर्ष 2017 में पेश सीएएटीएसए के तहत रूस से रक्षा और खुफिया लेन-देन करने वाले किसी भी देश के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है।

इसे 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे और 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मॉस्को के कथित हस्तक्षेप के जवाब में लाया गया था। पिछले दो दशकों में अपने सैन्य आधुनिकीकरण और विस्तार के चलते चीन दुनिया की सबसे प्रभावशाली ताकतों में से एक बनने की कगार पर पहुंच गया है। विशेष रूप से, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (पीएलएएन), संख्यात्मक रूप से सबसे बड़ी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का केंद्र बिंदु रही है। दक्षिण चीन सागर के ज्यादातर हिस्सों में पहले से आक्रामक गतिविधियां देखी जा रही हैं और अब सीसीपी पीएलएएन का इस्तेमाल हिंद महासागर में करना चाह रही है जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बिगाड़ सकता है।

किसी का भी समर्थन करें, लेकिन सुनक का नहीं : जॉनसन ने सहयोगियों से कहा

लंदन। (एजेंसी)।

ब्रिटेन के नये प्रधानमंत्री के लिए दौड़ के गति पकड़ने के बीच कार्यवाहक प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने सहयोगियों से कथित तौर पर कहा कि ''किसी का भी समर्थन कीजिए, लेकिन ऋषि सुनक का नहीं।'' मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई। सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के जॉनसन ने सात जुलाई को पार्टी के नेता के तौर पर इस्तीफा दे दिया था। 'द टाइम्स' अखबार की खबर में कहा गया है कि उन्होंने पार्टी का नेतृत्व हासिल करने की दौड़ में पिछड़ गये नेताओं से अनुरोध किया है कि वे पूर्व वित्त मंत्री एवं चांसलर सुनक का समर्थन नहीं करें, जो जॉनसन के अपनी ही पार्टी में समर्थन खोने के लिए जिम्मेदार हैं। एक सूत्र ने बताया कि जॉनसन विदेश मंत्री लिज ट्रस का समर्थन कराने को इच्छुक नजर आ रहे हैं, जिनका अनुमोदन उनके (जॉनसन के) कैबिनेट सहयोगियों जैकब रीस-मोग और नैडीन डोरिस ने किया है। जॉनसन ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर पेनी मोरडाउंट के लिए भी कथित तौर पर विकल्प खुले रखे हैं। मोरडाउंट कनिष्ठ व्यापार मंत्री हैं। खबर के मुताबिक, पूर्व चांसलर के इस्तीफे को अपने साथ कथित तौर पर विश्वासघात के रूप में देख रहे जॉनसन और उनका खेमा 'किसी का भी समर्थन कीजिए, लेकिन ऋषि सुनक का नहीं' के रूप में एक गुप्त अभियान चला रहा है। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री पद से उनके इस्तीफे ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट से जॉनसन की विदाई सुनिश्चित कर दी। अखबार ने एक सूत्र को उद्धृत करते हुए कहा, ''पूरी 10 डाउनिंग स्ट्रीट टीम ऋषि से नफरत करती है। वे उन्हें (जॉनसन को) अपदस्थ करने के लिए साजिद जाविद को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं। वे ऋषि को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्हें लगता है कि वह महीनों से इसकी साजिश रच रहे थे।'' गौरतलब है कि सुनक संसद के टोरी (कंजर्वेटिव) सदस्यों द्वारा किये गये प्रथम दो चरण के मतदान में विजेता रहे हैं। इस बीच, जॉनसन के एक सहयोगी ने इस दावे को खारिज कर दिया कि वह (जॉनसन) सुनक के अलावा किसी को

भी अपना उत्तराधिकारी बनते देखना चाहते हैं। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि निवर्तमान प्रधानमंत्री सुनक के विश्वासघात करने से नाराज हैं। वहीं, सुनक के खेमे ने इन सुझावों को तवज्जो नहीं देने की कोशिश की कि उनका मजबूत समर्थन टोरी सांसदों के अतिरिक्त नहीं है।सुनक का समर्थन कर रहे टोरी सांसद रिचर्ड होल्डेन ने कहा, ''उम्मीद है कि हम आगे बढ़ेंगे।

वनडे सीरीज के निर्णायक मुकाबले में आज भारतीय टीम का पूरा दरोमदार बल्लेबाजी पर

कोहली का खराब प्रदर्शन टीम के लिए चिंता का कारण

मैनचेस्टर (एजेंसी)।

इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम को पिछले मैच में 100 रन से करारी हार मिली थी। टीम रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के निर्णायक तीसरे वनडे में बल्लेबाजी रणनीति में थोड़ा बदलाव करना चाहेगी। रोहित शर्मा की अगुआई वाली टीम ने हाल में समाप्त हुई टी20 सीरीज के दौरान आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, जिससे काफी हद तक सफलता भी मिली. लेकिन जिस तरीके से दूसरे वनडे में टीम ने 247 रन के कम स्कोर के लक्ष्य का पीछा किया, उस देखकर लगता है कि काफी कुछ किया जा सकता है। हालांकि मैदान का रिकॉर्ड टीम इंडिया के पक्ष में नहीं है। यहां पर खेले गए अंतिम तीनों वनडे मैच इंग्लैंड ने जीते हैं। रोहित और शिखर धवन की ओपनिंग जोड़ी रीस टॉप्ली और डेविड विली की स्विंग के आगे रक्षात्मक हो गई थी। फिर विराट कोहली की लगातार असफलता से टीम की समस्या और बढ़ गई। इसकारण टीम बल्लेबाजी के तरीके में बदलाव कर सकती है और लक्ष्य का पीछा करने के लिए मानसिकता में बदलाव करना होगा। ओवल में पहले मैच में हालांकि जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट लेकर अकेले दम पर टीम को जीत दिलाई थी।

रोहित ने दूसरे मैच के बाद कहा कि मैं चाहता हूं कि खिलाड़ी टीम की भूमिका देखने के बजाय देखें कि वे अपने खेल के बारे में कुछ अलग कर सकते हैं। अगर वे उस स्थिति से टीम को बाहर निकालते हैं, तब सोचिये कि उनके आत्मविश्वास में इससे कितनी बढ़ोतरी होगी। टी20 मैच में शुरू से तेज खेलने का तरीका शानदार रहा और ऐसा नहीं है कि यह 50 ओवर के फॉर्मेट में काम नहीं कर सकता।

वहीं इंग्लैंड की स्टार सुसज्जित बल्लेबाजी लाइन अप भी पहले 2 मैचों में पूरी तरह से फॉर्म से बाहर दिखा और जिससे लगा कि मेजबान टीम में जोस बटलर, जॉनी बेयरस्टो, जेसन रॉय, बेन स्टोक्स और लियाम लिविंगस्टोन जैसी खिलाड़ी रंग में नहीं दिखे। ओल्डट्रेफर्ड पर सुबह होने वाले इस वनडे में हालांकि बल्लेबाजी चुनौतीपूर्ण होगी जहां गेंद काफी 'मूव' करती है और भारत को यहां 2019 में वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मिली हार भी ध्यान में रहेगी। ज्यादातर मैचों में रोहित का तरीका परेशानी भरा नहीं है, लेकिन मुख्य कोच राहुल द्रविड़ की अगुआई वाला भारतीय टीम मैनेजमेंट के अपने ही मुददा होगा। जिसमें यह भी कि 37 वर्षीय धवन अगले साल होने वाले 2023 वनडे वनडे वर्ल्ड कप में उनकी पसंद हैं, यहां नहीं। यह बाएं हाथ का खिलाड़ी रोहित और कोहली के अलावा काफी रन जुटाता रहा है। ऐसा इसलिए भी है, क्योंकि वे पारी का आगाज करते हैं।

वनडे वर्ल्ड कप में अभी 15 महीने का समय बाकी है, इस पर गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है कि रोहित, धवन और कोहली आगे भारत के पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के खिलाड़ी हो सकते हैं। कोहली निश्चित रूप से इस मैच के बाद एक महीने लंबे ब्रेक के लिए तैयार होने वाले हैं। इसके बाद खराब प्रदर्शन से निकलने के बारे में कोई प्लान भी बनाएंगे। जहां तक भारत के गेंदबाजी आक्रमण का संबंध है, तब उसने अभी तक 5 सफेद गेंद के मैचों में से 4 में तो उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन किया है।

जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की और मोहम्मद शमी ने अकसर विकेट चटकाने वाली गेंद फेंकी हैं। युजवेंद्र चहल ने अपनी तकनीक में थोड़ा बदलाव कर थोड़ी और धीमी गेंद फेंक रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा लेंथ से उछाल हासिल करने की काबिलियत को देखते हुए बेहतर ही होगा और हार्दिक पंड्या की गेंदबाजी लय से निश्चित रूप से भारतीय खेमे के चेहरों पर मुस्कान वापस आई है। चिंता का विषय केवल रवींद्र जडेजा की बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी है, जो अब तक फॉर्म में नहीं दिखे हैं। जडेजा बल्लेबाजी ऑलराउंडर के रूप में नजर आ रहे हैं।

एथलेटिक्स लीड विश्व चैम्पियनशिप: लंबी कूद के फाइनल में श्रीशंकर

यूजीन (अमरीका) (एजेंसी)।

भारत के मुरली श्रीशंकर (भारत में शनिवार सुबह) को विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के पुरुष लंबी कूद फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए। विश्व रैंकिंग में 13वें नंबर के खिलाफ श्रीशंकर ने 8.00 मीटर के सातवें सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ फाइनल में जगह बनाई। श्रीशंकर के साथ उनके हमवतन जेस्विन एल्ड्रिन (7.79 मीटर) और मोहम्मद अनीस यहया (7.73 मीटर) भी थे लेकिन वह पदक राउंड में जगह नहीं बना पाए। श्रीशंकर शनिवार (भारत में रविवार सुबह) होने वाले फाइनल में अकेले भारतीय होंगे। नियमों के अनुसार, 8.15 मीटर की कूद लगाने वाले एथलीट्स या दोनों समूहों के शीर्ष-12 फाइनल में जगह बनाने के योग्य थे। जापान के युकी हाशियोका (8.18 मीटर) और अमेरिका के मार्किवस डेंडी (8.16 मीटर) सहित केवल दो एथलीट ही मानक को पूरा करने में सक्षम थे। इसी बीच, भारत के अविनाश साबले ने विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के पहले दिन शनिवार को 3000 मीटर स्टीपलचेज फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। साबले ने 8.18.75 के समय के साथ तीसरा स्थान हासिल कर फाइनल में जगह बनाई। तीन हीट में से प्रत्येक के शीर्ष तीन और अगले छह सबसे तेज खिलाड़ियों ने फाइनल में जगह बनाई, जो सोमवार (भारत में मंगलवार सुबह) को आयोजित किया जाएगा। दोहा में फाइनल में पहुंचे 27 वर्षीय साबले वर्तमान में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं। उन्होंने पिछले महीने रबात डायमंड लीग के फाइनल में 8.12.48 के साथ अपने ही पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड (8.16.21) को तीन सेकंड से मात दी थी। साबले ने 8वीं बार पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तो था। उन्होंने पहली बार 2018 में गोपाल सैनी द्वारा निर्धारित 8.30.88 के 37 वर्षीय रिकॉर्ड को अंतर राज्य चैंपियनशिप में 8.29.80 के समय के साथ तोड़ा था।

शिखर धवन भारतीय क्रिकेट में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते, और हर फार्मेट में बेहतर कर सकते : मांजरेकर

मुंबई (एजेंसी)।

भारतीय ओपनर शिखर धवन ने इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा सीरीज के द्वारा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की। उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी वनडे मैचों की सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी भी करनी है। इस स्टार सलामी बल्लेबाज की तारीफ भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने भी की है। मांजरेकर का मानना है कि धवन भारतीय क्रिकेट में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं और वनडे फॉर्मेट में वह हमेशा से सर्वश्रेष्ठ साबित हुए हैं।

धवन भले ही सीरीज के दूसरे वनडे में कुछ खास नहीं कर सके लेकिन केनिंग्टन ओवल मैदान पर हुए पहले वनडे में उन्होंने रोहित शर्मा के साथ अविजित शतकीय साझेदारी की। भारत ने उस मैच को 10 विकेट से जीता था। धवन ने मुकाबले में 54 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से नाबाद 31 रन बनाए। इसके पहले धवन ने आईपीएल में कुछ शानदार पारियां भी खेलीं। हालांकि उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टी20 टीम में जगह नहीं मिली। वह केवल 50 ओवर के फॉर्मेट में ही खेलते नजर आते हैं।

कपिल ने कोहली पर तंज कसते हुए कहा, उन्हें टीम चयनकर्ता आराम देना चाहते हैं, तब इसमें बुराई क्या

कोहली को अपने फार्म को वापस लेने का प्रयास करना चाहिए

नई दिल्ली (एजेंसी)।

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव, जिनके विराट कोहली को टी20 टीम से बाहर करने के बयान पर बवाल मचा था। उन्होंने वेस्टइंडीज दौरे के लिए टी20 टीम के ऐलान के बाद फिर ऐसी बात कही है, जिसपर फिर हंगामा मच सकता है। दरअसल, बीसीसीआई ने एक दिन पहले वेस्टइंडीज दौरे के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान किया था। इसमें विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह का नाम नहीं था। बीसीसीआई ने इन दोनों खिलाड़ियों के इस दौरे से बाहर होने की कोई वजह भी नहीं जाहिर की हैं। लेकिन, कई

मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि दोनों सीनियर खिलाड़ियों को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया है। हालांकि, कपिल देव की इस मसले पर अलग राय है।

कपिल देव ने कहा, मैं यह नहीं कह सकता कि विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी को बाहर कर दिया जाना चाहिए। वह बहुत बड़े खिलाड़ी हैं. अगर आपने कहा है कि उन्हें सम्मान देने के लिए आराम दिया गया है, तब इसमें कोई बुराई नहीं है। कोहली ग्रोइन इंजरी के कारण इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में नहीं खेले थे। लेकिन, लॉर्ड्स में हुए दूसरे वनडे में उन्होंने टीम में वापसी की। इसके बाद एक बात तो मोटे तौर पर साफ हो गई है कि वेस्टइंडीज दौरे पर उनका न जाने का सीधे चोट से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वहां इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा वनडे खेल चुके है। उन्होंने 50 ओवर फील्डिंग की और फिर बल्लेबाजी के लिए भी उतरे। लेकिन 16 रन बनाकर आउट हो गए.

भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर थ्री पॉजिशंस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता

चांगवन। भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप की 50 मीटर थ्री पॉजिशंस स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तोमर ने हंगरी के जलान पेकलर को पछाड़कर पोडियम में शीर्ष स्थान पर कब्जा किया। वह क्वालीफिकेशन दौर में भी 593 अंक के स्कोर से शीर्ष पर रहे थे। वहीं हंगरी के अनुभवी इस्तवान ने कांस्य पदक जीता। रैंकिंग राउंड में तोमर ने पहली दो नीलिंग एवं प्रोन पॉजिशंस स्पर्धा में परफेक्ट स्कोर बनाया। लेकिन अंतिम स्टैंडिंग पॉजिशंस में अपने सभी सात अंक गंवा दिए। एक अन्य भारतीय चैन सिंह सातवें स्थान पर रहे।

इंग्लिश काउंटी केंट के लिये आठ मैच खेलेंगे नवदीप सैनी

केंट। भारत के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी इंग्लिश काउंटी टीम केंट के लिये मौजूदा सत्र में आठ मैच खेलेंगे। सैनी इस काउंटी के लिये खेलने वाले राहुल द्रविड़ के बाद भारत के दूसरे टेस्ट क्रिकेटर होंगे। वह 96 नंबर की शर्ट पहनेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ इस महीने की शुरूआत में बर्मिंघम टेस्ट से पहले वह भारतीय टीम के साथ नेट गेंदबाज के जौर पर थे। केंट काउंटी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा ,'' केंट क्रिकेट को तीन काउंटी चैम्पियनशिप मैचों और पांच रॉयल लंदन कप मैचों के लिये भारत के अंतरराष्ट्रीय तेज गेंदबाज नवदीप सैनी के साथ करार की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।''सैनी भारत के लिये तीनों प्रारूप खेल चुके हैं। उन्होंने अगस्त 2019 में पदार्पण किया था।

स्टोक्स को दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला में आराम

लंदन। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स को टीम के कार्यभार प्रबंधन के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टी20 श्रृंखला में आराम दिया गया है। भारत के खिलाफ मौजूदा वनडे श्रृंखला में खेल रहे स्टोक्स 19 जुलाई से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 50 ओवर के मैचों में भी खेलेंगे जिसके बाद उन्हें 27 जुलाई से शुरू हो रही टी20 श्रृंखला में आराम दिया जायेगा। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, ''इंग्लैंड पुरूष टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स के कार्यभार और फिटनेस प्रबंधन के लिये वह वाइटैलिटी टी20 सीरीज और 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे जो अगले महीने शुरू होंगे।

बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु का धमाल, सिंगापुर ओपन के फाइनल में पहुंचीं

सिंगापुर (एजेंसी)।

सिंगापुर ओपन में भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने धमाल मचा दिया है। दो बार की ओलंपिक विजेता पीवी सिंधु ने फाइनल में जगह बना ली है। सिंधू ने सेमीफाइनल में जापान की गैर वरीय साइना कावाकामी को सीधे सेटों में हराया। बता दें कि फाइनल के लिए सिंधु और साइना कावाकामी के बीच सेमीफाइनल हुआ, जो सिंधु ने आसानी से जीत लिया। जापानी स्टार कावाकामी एक भी बार सिंधु पर भारी पड़ती नजर नहीं आईं।

खिताबी मुकाबले में सिंधु की सीधी टक्कर जापान की आया ओहोरी या चीन की जी यी वांग से होगा। जापान की आया ओहोरी ने क्वार्टरफाइनल में भारतीय स्टार साइना नेहवाल को ही शिकस्त दी थी। साइना को जापान की आया ओहोरी ने हराया। ओहोरी को खिताबी मुकाबले में सिंधु से भिड़ने के लिए अब जी यी वांग को हराना होगा। पीवी सिंधु ने चीन की हान यूइ को एक घंटे से अधिक चले मुकाबले में हराकर सिंगापुर ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। दुनिया की सातवें नंबर की खिलाड़ी ने एक गेम गंवाने के बाद जीत दर्ज की थी। सिंधु के लिए जितना मुश्किल क्वार्टरफाइनल मुकाबला रहा था, उतना ही आसान सेमीफाइनल रहा। उन्होंने सिर्फ 30 मिनट में कावाकामी को शिकस्त दे दी।

सिंधु लगातार शानदार फॉर्म में दिख रही हैं। उन्होंने इसी साल मार्च में हुए स्विस ओपन के बाद पहली बार किसी टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई है। सिंधु ने स्विस खिताब पर कब्जा जमाया था। उन्होंने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में थाईलैंड की बुसानन ओंगबामरुंगफान को 21-16, 21-8 से हराया था।

बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतेंगे: हॉकी उपकप्तान हरमनप्रीत

बेंगलुरु। आत्मविश्वास से भरे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के उपकप्तान हरमनप्रीत सिंह को उम्मीद है कि टीम आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में ऑस्ट्रेलिया के स्वर्णिम अभियान को रोकने में सफल रहेगी। हॉकी 1998 में राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा बना और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इसके बाद पुरुषों की प्रतियोगिता में सभी 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। हरमनप्रीत ने भरोसा जताया कि उनकी टीम बर्मिंघम में पासा पलटने में सफल रहेगी। उन्होंने कहा कि टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हमने एफआईएच हॉकी प्रो लीग में भी अच्छा खेला और इसलिए टीम में आत्मविश्वास की कमी नहीं है। हम मैच जीतते रहना चाहेंगे। हम निश्चित रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण जीतने के लिए अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों के लिए हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हम अभ्यास सत्र के दौरान अपने खेल के कुछ विशेष पहलुओं पर काम कर रहे हैं। हमारा ध्यान एफआईएच हॉकी प्रो लीग में हुई गलतियों से सीखने पर है। इस ड्रैग-फ्लिकर ने कहा कि गेंद को गोल पोस्ट के पास ले जाकर उसे सफलतापूर्वक गोल में बदलना और रक्षापंक्ति की खामी भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है लेकिन टीम इन दोनों पहलुओं पर लगातार काम कर रही है। हॉग ने कहा कि हम लगातार अभ्यास मैच खेल रहे है। मुख्य टीम शिविर में शामिल अन्य खिलाडियों की टीम के खिलाफ खेल रही है। इन अभ्यास मैचों से हमें मैदान में आपसी समन्वय सुधारने में मदद मिली है। इससे हमें अपनी रणनीतियों को परखने का मौका भी मिल रहा है।

दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध वनडे-टी20 के लिए इंग्लिश टीम घोषित, हज यात्रा से वापिस आए आदिल राशिद

नई दिल्ली (एजेंसी)।

दक्षिण अफ्रीका बनाम इंग्लैंड के बीच वनडे-टी20 श्रंखला के लिए टीम घोषित हो गई है। दोनों देशों के बीच सीरीज की शुरुआत 19 जुलाई से हो रही है। दक्षिण अफ्रीका की टीम इंग्लैंड के दौरे पर आएगी जहां उसे तीन वनडे और इतने ही मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। इंग्लैंड ने जॉस बटलर की अगुवाई में वनडे के लिए 15 सदस्यीय और टी20 के लिए 14 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लेग स्पिनर आदिल राशिद की वापसी हुई हैं। वहीं, वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत बेन स्टोक्स को टी20 सीरीज के लिए आराम दिया गया है। भारत के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज में खेल रहे स्टोक्स 19 जुलाई से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 50 ओवर के मैचों में भी खेलेंगे जिसके बाद उन्हें 27 जुलाई से शुरू हो रही टी20 सीरीज में आराम दिया जाएगा। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, 'इंग्लैंड पुरुष टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स के कार्यभार और फिटनेस प्रबंधन के लिए वह वाइटैलिटी टी20 सीरीज और 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे जो अगले महीने शुरू होंगे।'

इंग्लैंड के लेग स्पिनर आदिल राशिद की टीम में वापसी हुई है। वह भारत के खिलाफ लिमिटेड ओवर सीरीज में नहीं खेल रहे हैं। उन्हें इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने हज यात्रा के लिए छुट्टी दी थी। इंग्लैंड के 23 वर्षीय तेज गेंदबाज मैथ्यू पोट्स को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम में जगह मिली है। पोट्स ने भारत के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट में चार विकेट झटके थे। पहली पारी में उन्होंने विराट कोहली को बोल्ड करके सनसनी मचा दी थी। वह अफ्रीका के खिलाफ वनडे डेब्यू कर सकते हैं।

इंग्लैंड की वनडे टीम: जॉस बटलर (कप्तान), मोईन अली, जॉनी बेयरस्टो, ब्राइडन कॉर्स, सैम करेन, लियाम लिविंगस्टोन, क्रेग ओवर्टन, मैथ्यू पोट्स, आदिल राशिद, जो रूट, जेसन रॉय, फिल साल्ट, बेन स्टोक्स, रीस टॉप्ली और डेविड विली।

टी20 विश्व कप2022 में अपना स्थान जिम्बाब्वे ने किया पक्का, 16 टीमें दिखाएंगी अपना खेल कौशल

नई दिल्ली। नीदरलैंड और जिम्बाब्वे ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप स्पर्धा के क्वालीफायर बी के अपने सेमीफाइनल में क्रमशः अमेरिका और पपुआ न्यू गिनी को पराजित कर आईसीसी टी20 विश्व कप में स्थान पक्के किए। नीदरलैंड ने अमेरिका को सेमीफाइनल में सात विकेट से पराजित किया। उसने अमेरिका को 19.4 ओवर में 138 रन पर समेट दिया था। जिम्बाब्वे ने पपुआ न्यू गिनी को 27 रन से शिकस्त दी। टूर्नामेंट के मेजबान जिम्बाब्वे का पहले बल्लेबाजी करने का फैसला फायदेमंद साबित हुआ। रेगिस चाकाब्वा और कप्तान क्रेग इर्विन की अनुभवी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत कराई। चाकाब्वा ने आक्रामक रवैया अपनाते हुए मैच का पहला चौका पहले ही ओवर में लगा दिया जिसके बाद उन्होंने सेमा कामीवा पर लगातार तीन चौके जड़ दिए। एक ओवर बाद उन्होंने एक छक्का जड़ा जिससे वह और खतरनाक दिख रहे थे। लेकिन उनकी 19 गेंद में 30 रन की आक्रामक पारी का अंत सेसे बाऊ ने किया। विकेट गिरने से भी जिम्बाब्वे की रनों की रफ्तार पर लगाम नहीं लगी। इर्विन और वेस्ले माधवेरे ने लगातार अंतराल पर बाउंड्री लगायी। 10वें ओवर के अंत में जिम्बाब्वे का स्कोर एक विकेट पर 90 रन था। अगले पांच ओवर में मेजबान ने इर्विन (38) और माधवेरे (29 गेंद में 42 रन) के विकेट गंवा दिए। मध्यक्रम ने उपयोगी रन जुटाकर टीम को 20 ओवर में पांच विकेट पर 199 रन का मजबूत स्कोर बनाने में मदद की। जिम्बाब्वे ने पहली ही गेंद पर पपुआ न्यू गिनी का पहला विकेट झटक लिया।

चोट के कारण राष्ट्रमंडल खेलों में नहीं खेल पाएंगे तेजिंदरपाल सिंह तूर

नई दिल्ली (एजेंसी)।

शीर्ष भारतीय गोला फेंक एथलीट तेजिंदरपाल सिंह तूर अमरीका के यूजीन में चल रही विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप से पहले लगी 'ग्रोइन' चोट के कारण बर्मिंघम में होने वाले आगामी राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर हो गए। एशियाई रिकॉर्डधारी तूर इस चोट के कारण यूजीन में अपनी स्पर्धा में हिस्सा नहीं ले सके। उन्हें यह चोट 4 दिन पहले अमरीका में चुला विस्टा में लगी जहां भारतीय टीम ने थोड़े समय के लिए ट्रेनिंग अभ्यास किया था। उन्होंने स्पर्धा के लिए कुछ अभ्यास थ्रो फेंके लेकिन दर्द के कारण फिर हटने का फैसला किया।

तूर ने कहा- नहीं, मैं इस ग्रोइन चोट के कारण राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। उन्होंने कहा- 4 दिन पहले चुला विस्टा में मेरे ग्रोइन मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था और इससे मेरे प्रदर्शन पर काफी असर पड़ा। मैं रिहैबिलिटेशन करूंगा और भविष्य की प्रतियोगिताओं में मजबूत वापसी करूंगा। तूर को 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चलने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 36 सदस्यीय भारतीय टीम में चुना गया था लेकिन उनका चयन कजाखस्तान में एक प्रतियोगिता के प्रदर्शन पर निर्भर था। वह भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) द्वारा तय किए गए 20.50 मीटर के क्वालीफाइंग मानक से चूक गए थे। वह पिछले महीने चेन्नई में राष्ट्रीय अंतरराज्यीय चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के दौरान 20.34 मीटर का थ्रो ही कर पाए थे।

नौ जुलाई को चुला विस्टा में एक प्रतियोगिता में उन्होंने 19.96 मीटर का थ्रो किया था। तूर को हालांकि कोसानोव मेमोरियल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लिये बिना ही भारत लौटना पड़ा क्योंकि उन्हें विश्व चैम्पियनशिप के लिये वीजा औपचारिकतायें पूरी करनी थीं। तूर ने कहा कि उन्हें डर है कि चोट बढ़ सकती है इसलिये उन्होंने अंतिम समय में विश्व चैम्पियनशिप से हटने का फैसला किया।

तूर के नाम के आगे 'नो मार्क' (एनएम) लिखा हुआ था। उन्होंने कहा कि मुझे यह (ग्रोइन) चोट

चुला विस्टा (अमेरिका) पहुंचने के बाद लगी थी। मैंने यह देखने के लिए दर्द अभी है या नहीं, कुछ 'वार्म-अप' थ्रो भी फेंके। थ्रो करते हुए मुझे दर्द महसूस हो रहा था इसलिए मैंने स्पर्धा से हटने का फैसला किया। एशियाई खेलों के मौजूदा स्वर्ण पदक विजेता ने कहा कि अगर मैं स्पर्धा में हिस्सा लेता तो मेरी चोट बढ़ सकती थी और यह 'थर्ड ग्रेड' की चोट बन सकती थी और मैं सात-आठ महीने के लिए बाहर हो जाता।

'रेवड़ी कल्चर' देश के विकास के लिए घातक : पीएम मोदी

जालौन, 16 जुलाई (एजेन्सी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मुफ्त में सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली राजनीति की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि यह रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है।

मोदी ने शनिवार को जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव में लगभग 14,850 करोड़ रुपये की लागत से बने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ये रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एअरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनाएंगे।

उन्होंने कहा, रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर, उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है, रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है।

मोदी ने कनेक्टिविटी की कमी के लिए उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों पर निशाना साधा और कहा कि डबल-इंजन की सरकार अब तेजी से बेहतर कनेक्टिविटी के साथ राज्य में बड़ा बदलाव सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी तीन-चार घंटे कम हो गई है, लेकिन इसका फायदा इससे कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेसवे यहां सिर्फ वाहनों को गति नहीं देगा, बल्कि यह पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को गति देगा।

प्रधानमंत्री ने कहा, बुंदेलखंड की एक और चुनौती को कम करने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए हम जल जीवन मिशन पर काम कर रहे हैं।

उन्होंने लोगों, खासकर युवाओं को रेवड़ी कल्चर के प्रति आगाह किया और कहा कि यह देश के विकास के लिए बहुत घातक हो सकता है।

मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून-व्यवस्था और तेजी से सुधार के साथ बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता डबल इंजन शब्द का इस्तेमाल केंद्र और राज्य में पार्टी के सत्ता में होने का उल्लेख करने के लिए करते हैं।

मोदी ने कहा कि देश जिस विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है उसके मूल में दो पहलू हैं- इरादा और मर्यादा। उन्होंने कहा, हम न केवल वर्तमान के लिए नयी सुविधाएं बना रहे हैं बल्कि देश का भविष्य भी बना रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, जिस उत्तर प्रदेश में रायबरेली रेल कोच फैक्ट्री, सिर्फ डिब्बों का रंग-रोगन करके काम चला रही थी, उस उत्तर प्रदेश में अब बुनियादी ढांचे पर इतनी गंभीरता से काम हो रहा है कि उसने अच्छे-अच्छे राज्यों को भी पछाड़ दिया है। पूरे देश में अब उत्तर प्रदेश की पहचान बदल रही है।

मोदी ने 29 फरवरी, 2020 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। इस एक्सप्रेसवे का काम 28 महीने के भीतर पूरा कर लिया गया है। उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी को स्थानीय बुंदेली वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया।

296 किलोमीटर लंबे इस चार लेन वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईआईडीए) के तत्वावधान में लगभग 14,850 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है और आगे चलकर इसे छह लेन तक भी विस्तारित किया जा सकता है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले में भरतकूप के पास गोंडा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग-35 से लेकर इटावा जिले के कुदरैल गांव तक फैला हुआ है, जहां यह आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ मिल जाता है। यह एक्सप्रेसवे सात जिलों यानी चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है।

बयान के मुताबिक, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस इलाके की कनेक्टिविटी में सुधार के साथ-साथ आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के ढेरों अवसर सृजित होंगे। बांदा और जालौन जिलों में इस एक्सप्रेसवे के समीप औद्योगिक गलियारा बनाने का काम पहले ही शुरू हो चुका है।

प्रधानमंत्री मोदी के उत्तर प्रदेश आगमन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत करते हुए ट्वीट किया, महान ऋषि-मुनियों की तपोस्थली, सृजन की धरा, विभिन्न संस्कृतियों की संगमस्थली, उत्तर प्रदेश की क्रांति भूमि पर नए भारत के शिल्पकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।

नि:शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा मुफ्त की 'रेवड़ी' नहीं : अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली, 16 जुलाई (एजेन्सी)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार की निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बिजली की योजनाएं मुफ्त की रेवड़ी नहीं हैं, बल्कि भारत को दुनिया का नंबर एक देश बनाने की नींव रखने का प्रयास है।

उन्होंने कहा कि अगर ईश्वर की इच्छा से वह ऐसा करने की स्थिति में हैं, तो देश में सभी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त होंगी।

इससे पूर्व दिन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुफ्त में सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली राजनीति की तीखी आलोचना करते हुए कहा था कि यह रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है।

बिना किसी का नाम लिए केजरीवाल ने कहा, मैं आपको बताऊंगा कि कौन रेवड़ी बांट रहा है और मुफ्त सौगात दे रहा है। दोस्तों का हजारों करोड़ रुपये का कर्ज माफ करना और दोस्तों के लिए विदेशी दौरों से हजारों करोड़ रुपये का ठेका लेना मुफ्त उपहार है।

केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, फरिश्ते योजना के माध्यम से हमने हादसों में घायल हुए लोगों का समय पर मुफ्त इलाज कर 13,000 लोगों की जान बचाई। उनके परिवार वालों से पूछिए कि केजरीवाल रेवड़ी बांट रहे हैं या कोई नेक काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आज देश में दो तरह की राजनीति हो रही है- एक ईमानदारी वाली और दूसरी भ्रष्टाचार। उन्होंने कहा कि सभी को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देकर भारत को दुनिया का नंबर एक देश बनाने के लिए एक मजबूत नींव रखने की जरूरत है।

लोकसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, बोले- सभी दलों ने सहयोग का भरोसा दिया

नई दिल्ली, 16 जुलाई (एजेन्सी)। संसद का मानसून सत्र सोमवार यानी 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को सभी राजनीतिक दलों की अहम बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने सभी नेताओं को संसद सत्र की तैयारियों के बारे में बताया। बैठक में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, डीएमके सांसद टीआर बालू, केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता समेत प्रहलाद जोशी, भाजपा सांसद अर्जुन राम मेघवाल, वाईएसआरसीपी सांसद पीवी मिथुनरेड्डी, आरएलजपी सांसद पशुपति कुमार पारस और अन्य पार्टियों के सांसद शामिल हुए। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति, शिवसेना, एनसीपी, बसपा, सपा, तेलुगु देशम पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, बीजद और वामदलों ने बैठक में शिरकत नहीं की।

बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सत्र 18 जुलाई से प्रारंभ होकर 12 अगस्त तक चलेगा। सत्र के संबंध में आज सभी दल के नेताओं से विचार विमर्श हुआ। मैंने सभी दलों के नेताओं से आग्रह किया है कि देश के हित में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें। सदन बिना हस्तक्षेप के मर्यादा के साथ चले। सभी दलों के नेताओं ने आश्वस्त किया है कि हम सदन कि कार्यवाही में सहयोग करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं ने महंगाई, अग्निपथ योजना और डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट पर चर्चा की मांग उठाई।

बैठक में चर्चा हुई कि संसद सत्र के दौरान किन मुद्दों को उठाया जाएगा। इस दौरान अलग-अलग विधेयकों पर चर्चा के लिए कितना समय दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस दौरान असंसदीय शब्दों की हाल में जारी सूची जैसे मामलों पर भी चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष हर संसद सत्र की शुरुआत से पहले सर्वदलीय बैठक करते हैं। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा।

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को कहा कि विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में संसद के मानसून सत्र में अग्निपथ सेना भर्ती योजना, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग की। चौधरी ने यह बात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद कही।

सर्वदलीय बैठक शनिवार शाम को संसदीय परिसर में हुई और इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के सदन के नेता शामिल हुए। चौधरी ने कहा कि हमने लोकसभा अध्यक्ष बिरला से सदन में अग्निपथ, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कराने और इसके लिए विपक्ष को पर्याप्त समय देने की मांग की।

यूपी में मदरसा पर चला योगी सरकार का बुलडोजर, अवैध निर्माण को गिराया

अमरोहा, 16 जुलाई (एजेन्सी)। यूपी में एक बार फिर अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू हो गई। इसका नजारा यूपी के अमरोहा में देखने को मिला है। यहां अवैध रूप से बनाए गए मदरसे के अवैध निर्माण को योगी सरकार के बुलडोजर ने शनिवार को ध्वस्त कर दिया। जिला प्रशासन ने शनिवार को बताया कि शहर में अवैध रूप से बनाए गए मदरसों की लगातार मिल रहीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने ऐसे तमाम स्थलों को चिह्नित कर कार्यवाही शुरू कर दी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जनपद के रहरा थाना क्षेत्र के गांव जेबड़ा में अवैध रूप से बने मदरसे पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया।

पहले इसे जमीन पर पशु बांधे जाते थे, बाद में यहां मदरसा चलने लगा। उसके बाद अब यहां सामूहिक रूप से नमाज का सिलसिला जारी रहने का विरोध करते हुए ग्रामीणों द्वारा अनेकों बार उच्चाधिकारियों से शिकायत की जा चुकी थी। आरोप है कि प्रशासन द्वारा शिकायतों को हर बार अनसुना कर दिया जाता था। लगातार शिकायतें मिलने पर जांच पड़ताल के बाद जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी के निर्देश पर शनिवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है।

सुबह जिलाधिकारी के निर्देश पर भारी पुलिस एवं पीएसी बल व राजस्व टीम के साथ उप जिलाधिकारी द्वारा ग्राम जेवड़ा में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए मदरसे को जेसीबी चलाकर गिराया गया। यह मदरसा ग्राम समाज की भूमि पर पहले पशुओं को बांधना शुरू किया था, बाद में धीरे धीरे अवैध रूप से मदरसा संचालित किया जाने लगा। अब नमाज भी पढ़ी जा रही थी।

अहमद पटेल के जरिए तीस्ता को 30 लाख दिए : संबित पात्रा

नई दिल्ली, 16 जुलाई (एजेन्सी)। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और तीस्ता सीतलवाड़ पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात दंगों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तीस्ता सीतलवाड़ को 30 लाख रुपए दिए।

गुजरात दंगे को लेकर गठित एसआईटी द्वारा कोर्ट के सामने रखे गए एफिडेविट का हवाला देते हुए भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोनिया गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि मीडिया में आए एफिडेविट के अनुसार, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने तत्कालीन राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल के जरिए 30 लाख रुपये तीस्ता सीतलवाड़ को भिजवाए थे।

पात्रा ने इस मामले में सोनिया गांधी से जवाब देने की मांग करते हुए कहा कि अहमद पटेल जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने तो केवल पैसों की डिलीवरी की थी, इसलिए इस मामले पर सोनिया गांधी को सामने आकर अपनी सफाई रखनी चाहिए।

पात्रा ने कहा कि गुजरात दंगे 2002 में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को अपमानित करने की चेष्टा कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत की थी, परत दर परत उसकी सच्चाई सामने आ रही है।

इस संदर्भ में गठित एसआईटी द्वारा कोर्ट के सामने रखा गया, एफिडेविट यह कहता है कि तीस्ता सीतलवाड़ और उसके सहयोगी मानवता के तहत नहीं, बल्कि राजनीतिक मंसूबे के तहत तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने और गुजरात सरकार को अस्थिर करने के मंसूबे के तहत काम कर रहे थे।

इस काम के लिए तीस्ता सीतलवाड़ को पैसा दिया गया था। पहली किस्त के रूप में सोनिया गांधी ने अहमद पटेल के जरिए 30 लाख रुपये तीस्ता सीतलवाड़ को दिए थे। इसके बाद न जाने कितने करोड़ों रुपये सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को अपमानित और बदनाम करने के लिए और केवल राहुल गांधी को प्रोमोट करने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ को दिए।

प्रतियोगी परीक्षा तैयारी का पूरा खर्च उठाएगी सरकार : हेमंत सोरेन

रांची, 16 जुलाई (एजेन्सी)। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के नौजवानों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने कहा कि राज्य के नौजवानों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का पूरा खर्च सरकार उठायेगी। जल्द ही सरकार जेपीएससी, यूपीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ आदि सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का खर्च उठाने के लिये कानून लाने जा रही है। अब पैसों के अभाव में युवाओं को तैयारी बीच में ही नहीं छोड़नी पड़ेगी। मुख्यमंत्री शनिवार को मोरहाबादी मैदान में निजी क्षेत्र के अंतर्गत नियोजन -सह- नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बोल रहे थे।

सीएम ने कहा कि आपकी सरकार, युवाओं की सरकार है। केंद्र सरकार हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में सफर का अवसर देने की बात कहती है, लेकिन हमारी सरकार ने कोरोना काल में विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिकों को हवाई जहाज से वापस लाकर यह काम पहले ही कर दिया है। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लाई गई। विदेशों में पढ़ाई का खर्च उठाने की योजना बनी। रिकॉर्ड समय में जेपीएससी की परीक्षा की प्रक्रिया पूरी कराई गई। गरीब भी जेपीएससी परीक्षा दे सके इसके लिये फार्म की कीमत 700-800 रुपये से घटाकर 50 से 100 रुपये कराया। पहली बार नियुक्ति नियमावली बनाकर नौकरी दे रहे हैं। लेबोरेट्री में वैज्ञानिकों और कृषि पदाधिकारियों की पहली बार नियुक्ति हुई और खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति जैसे कदम उठाये जा चुके हैं।

सरकार रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है।

सीजेआई का सरकार पर कटाक्ष

'न्यायिक सिक्तियों को न भरना लंबित मामलों का प्रमुख कारण'

नई दिल्ली, 16 जुलाई (एजेन्सी)। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एन वी रमना ने न्यायपालिका में बड़ी संख्या में लंबित मामलों के लिए केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा न्यायिक रिक्तियों को न भरना मामलों के लंबित होने का प्रमुख कारण है। सीजेआई की प्रतिक्रिया जयपुर में अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक में कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के संबोधन के बाद आई।

सीजेआई एन वी रमना ने कहा, 'यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एक या दो चीजों पर प्रतिक्रिया दूं, जिसका उल्लेख कानून मंत्री ने किया है। मुझे खुशी है कि उन्होंने पेंडेंसी के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा, 'जब हम न्यायाधीश भी देश से बाहर जाते हैं, तो हमें भी एक ही प्रश्न का सामना करना पड़ता है। एक मामला कितने साल चलेगा? आप सभी पेंडेंसी के कारणों को जानते हैं। मुझे इसके बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी जानते हैं कि प्रमुख महत्वपूर्ण कारण न्यायिक रिक्तियों को न भरना और न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार नहीं करना है।

सीजेआई ने अपने संबोधन में कहा, 'न्यायपालिका इन सभी मुद्दों को हल करने की कोशिश में हमेशा आगे है। मेरा एकमात्र अनुरोध है कि सरकार को रिक्तियों को भरने के साथ-साथ बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। नालसा सबसे अच्छा मॉडल है। यह एक सफलता की कहानी है। इसलिए उसी तर्ज पर, हमने पिछले मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में एक न्यायिक बुनियादी ढांचा प्राधिकरण का सुझाव दिया था। दुर्भाग्य से, इसे नहीं लिया गया था। हालांकि, मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि इस मुद्दे पर फिर से विचार किया जाएगा'।

सीजेआई ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का उदाहरण दिया जिसने पिछले साल लगभग 2 करोड़ मुकदमेबाजी और 1 करोड़ लंबित मामले निपटाए।

जेल में लगातार बढ़ रही कैदियों की आबादी पर चिंता व्यक्त करते हुए, सीजेआई ने कहा, 'भारत में हमारे पास 1378 जेलों में 6.1 लाख कैदी हैं। वे वास्तव में हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से एक हैं। जेल ब्लैक बॉक्स हैं। कैदी अक्सर अनदेखे, अनसुने नागरिक होते हैं।'

उन्होंने कहा, 'जेलों का विभिन्न श्रेणियों के कैदियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों से संबंधित। ई-जेल पोर्टल के तहत नई पहल कैदी के हितों को ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता की दिशा में एक कदम है। अब, एक कैदी के संबंध में सभी प्रासंगिक जानकारी, जैसे कि उनकी कैद और लंबित अदालती मामलों का विवरण, बस एक क्लिक दूर है।'

सीजेआई ने कहा, 'आज शुरू की गई एक और बड़ी पहल ई-मुलाकात की है। परिवार और समाज से लंबे समय तक अलगाव एक कैदी के मानसिक स्वास्थ्य और समाजीकरण पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। इस पहल के माध्यम से, कैदियों के परिवार और शुभचिंतक निरंतर उनसे संपर्क में रह सकते हैं। ई-पैरोल एप्लिकेशन एक और बड़ी पहल है जिसके माध्यम से कैदियों के पास सामाजिक अस्तित्व और बातचीत की निरंतरता हो सकती है।' सीजेआई ने कहा, 'पुलिस का प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की दिशा में एक कदम है। विवादों के लिए भी एडीआर की जरूरत होती है और इससे अदालतों पर बोझ कम होगा।' उन्होंने महात्मा गांधी के शब्दों के साथ निष्कर्ष निकाला और कहा, 'लोकतंत्र की मेरी धारणा यह है कि इसके तहत सबसे कमजोर को वही अवसर मिलना चाहिए जो सबसे मजबूत है।'

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक : सत्येन्द्र नाथ सिंह एवं मुद्रक: नूतन वर्मा द्वारा प्राइम प्रिंटर्स, प्रिमुला कॉटेज, चर्च रोड, गंगटोक से मुद्रित एवं रतना निवास, मेट्टो प्वाइंट, नेशनल हाईवे 10, गंगटोक (पूर्व सिक्किम) से प्रकाशित।
सम्पादक - सत्येन्द्र नाथ सिंह, कार्यकारी सम्पादक - अश्विनी आनंद, मोबाइल नं. : 9474355832, 9609024017, फोन नं. : 03592-204174, पोस्टल रजि. सं. : WB/SKM/110/07-09, e-mail ID : anugamini@gmail.com